RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

"सत्य" कदापि कटु नहीं होता है, स्वाद के मुताबिक न मिले, तो गले नहीं उतरता है।

आचार्य रामानुज जी

वर्ष-06, अंक - 07 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 09 नवम्बर 2023 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

दिल्ली ही नहीं पाक से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है प्रदूषण की समस्या पर कोई राजनीति नहीं चाहिए - पूर्व उप राष्ट्रपति

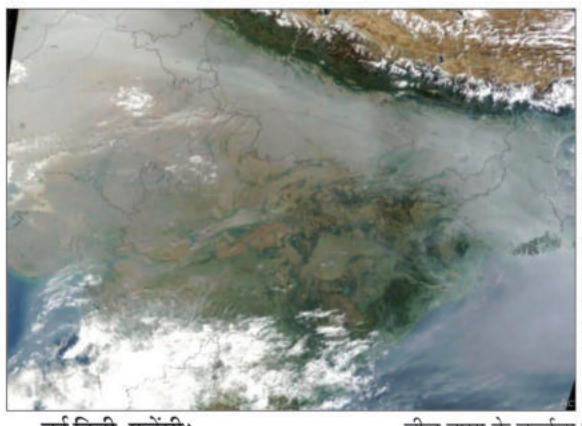

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसके चलते सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए ओला-उबर कैब पर रोक लगाने के साथ सभी स्कूलों को 9 दिन के लिए पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया है। वाहनों से फैला काला धुआं और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की हवा दमघोंटू हो रही है। इस बीच नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तस्वीर से पता चलता है कि पलूशन सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह धुंध पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण के बीच नासा के वर्ल्डव्यू ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पलूशन का काला और जहरीला धुआं पाकिस्तान के पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। डेटा से पता चलता है कि पलूशन की वजह उत्तर भारतीय राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी भी है।

नासा के आंकड़ों से पता चलता है कि, 29 अक्टूबर के बाद से खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है। पंजाब में 29 अक्टूबर को एक हजार 68 खेतों में आग लगने की घटनाओं के साथ पराली जलाने की घटनाओं में 740 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह आंकड़ा पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में सबसे अधिक है।

प्रदूषण में नंबर वन पर दिल्ली

बुधवार सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 तक पहुंच गया। नई दिल्ली पिछले छह दिनों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर है। वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने कई नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ओला-उबर पर रोक के साथ दिल्ली के सभी स्कूलों को 9 नवंबर से 18 नवंबर तक पूरी तरह बंद रखने की फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार निजी कारों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू भी करने वाली है।

नई दिल्ली।

पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि, केंद्र व दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को शहर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आम सहमति से एक फार्मूला विकसित करना चाहिए और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समस्या से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नायडू ने यहां चुनिंदा पत्रकारों के एक समूह से कहा, वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि, हालांकि यह मूल रूप से दिल्ली सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह केंद्र और राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे एक साथ आएं और इस समस्या से निपटने के लिए एक समय-सीमा आधारित कार्यक्रम विकसित करें।

नायडू ने कहा, मैं केंद्र सरकार सहित सभी से समन्वय, सहयोग, मिलकर काम करने और इससे निपटने के लिए एक आम सहमति वाला फार्मूला विकसित करने की अपील करता हूं। अब समय आ गया है कि समस्या पर ध्यान दिया जाए।

दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे पर पूर्व उपराष्ट्रपति

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर उन्होंने कहा, हालांकि मैं चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि कई पार्टियां इस बात की परवाह किए बिना घोषणाएं करती हैं कि उनके पास इस खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन हैं या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा गरीब तबकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने की यह घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है।

पूर्व उपराष्ट्रपति दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

महिला की अजीब गुहार, माँ बनने के लिए हाई कोर्ट से मांगी पति की एक महीने की रिहाई

भोपाल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जिसमें एक महिला ने मां बनने के लिए पति को रिहा करने की मांग की है। महिला ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से मांग की है कि, वह मां बनना चाहती है इसलिए उसके पति को एक महीने के लिए रिहा किया जाए। कोर्ट ने महिला की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिससे पता चल सके कि वह गर्भ धारण कर सकती है या नहीं। महिला का पति इस समय इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। महिला ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पति को एक महीने के लिए रिहा करने की गुहार लगाई है।

एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक महीने के लिए पति को जेल से रिहा करने की मांग की है ताकि वह बच्चा पैदा कर सके। याचिकाकर्ता महिला ने संतान प्राप्ति को अपना 'मौलिक अधिकार' बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने मेडिकल कॉलेज के डीन को विशेषज्ञ डॉक्टर की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर्स की टीम जांच करेगी की महिला गर्भ धारण के योग्य है या नहीं। मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

सुनवाई के जौरान महिला के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि, संतान पैदा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कैदियों के वैवाहिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया और कहा कि, याचिकाकर्ता को भी अपने पति से बच्चा पैदा करने का मौका दिया जाना चाहिए। महिला का पति किसी आपराधिक मामले में जेल में है।

चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका लेगा अडानी का सहारा

नई दिल्ली, एजेंसी।

श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अब अमेरिका भी भारत के साथ रणनीति बनाने में जुटा है। इसी के तहत अमेरिका ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की ओर से बनाए जा रहे पोर्ट में 553 मिलियन डॉलर के निवेश का फैसला लिया है। भारत और अमेरिका दोनों ही द्वीपीय देश में चीन के रणनीतिक प्रभाव को कम करना चाहते हैं। इस लिहाज से यह फैसला अहम है। चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर लोन दिए हैं। उसके कर्ज से ही कई बंदरगाहों और हाईवे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि वे श्रीलंका में अपना निवेश बढ़ाएं ताकि ड्रैगन का प्रभाव कम हो सके।

वहीं अमेरिकी निवेश से गौतम अडानी की कंपनियों को बड़ी ताकत मिलेगी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से आलोचना का शिकार हैं और शेयरों में गिरावट भी झेलनी पड़ी है। इस साल की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अमेरिकी सरकार ने आखिरी बार कोलंबो के एक टर्मिनल में ही निवेश किया था। उसके बाद अब वह गौतम अडानी के प्रोजेक्ट में रकम लगाने की तैयारी में है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका के पोर्ट में इस निवेश से हमारे देश की इंडो पैसेफिक क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर होती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते वर्ष श्रीलंका में 2.2 अरब डॉलर का निवेश किया था, जो किसी भी देश से ज्यादा था। अमेरिका तो लगातार श्रीलंका की इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि वह बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज ले रहा है। अमेरिकी अधिकारी कहते रहे हैं कि चीन से कर्ज के दुष्चक्र में श्रीलंका फंस रहा है और इसी के चलते वह आर्थिक संकट में आया है।

सर चढ़कर बोलने लगा चुनावी रंग, सबकी अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग

दोनों ही दल लगा रहे ऐड़ी चोटी का जोर, अब मतदाता मनाने में लगेंगे दीपावली

माही की गूंज, झाबुआ।

विधानसभा 2023 का चुनाव अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। शहरों के साथ ही गांवों, फलियों में प्रचार रथ अपने-अपने भोंगे लेकर प्रचार करते नजर आ रहे है। कहीं आम सभाएं चल रही है तो कहीं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन। यह सारी उठा पटक राजनीतिक दलों में जमकर देखने को मिल रही है। तमाम तरह के प्रयास जनता को रिझाने के लिए किए जा रहे है। मगर इस चुनाव के एन पहले दीपावाली का पांच दिवसीय त्यौहार इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के आड़े आ सकता है। यह दीपावली का त्यौहार अपने बाद किसकी दीपावली मनवाएगा और किसका दीवाला निकलवाएगा यह तो भविष्य के गर्त में है। जिले की जनता अब फिलहाल कम से कम पांच दिनों के लिए दीपावली के त्यौहार में व्यस्त रहने वाली है। मगर इस दीपावली राजनीतिक पार्टियों के भी अपने ही अलग गणित दिखाई पड़ रहे है। इन त्यौहारों के बीच ही पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं की जिले में सभाएं होना संभावित है। हालांकि पांच दिवसीय त्यौहार के बीच यह सभाएं कितनी सफल होगी इसके बारे में भी कुछ कहा तो नहीं जा सकता। मगर यह तय है कि, जनता इस बार दीपावली का त्यौहार जमकर मनाने वाली है। हो सकता है इस त्यौहार के बीच राजनीतिक दलों के समीकरण में उलट फैर हो जाए। क्योंकि 10 नवम्बर से शुरू होने जा रहे पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन 15 नवम्बर को होगा और 17 नवम्बर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। इस स्थिति में 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार थम जाएगा। तो जिस दिन मतलब 15 नवम्बर को जैसे ही जनता त्यौहार से निपटेगी वैसे ही चुनावी प्रचार रूक जाएगा। हां यह जरूर है कि, जैसा हम देखते सुनते आए कि, प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी खुद वन टू वन संपर्क कर प्रचार करेंगे। अंदर खाने पार्टियों के कार्यकर्ता भी घर-घर धोक देंगे। मगर खुले रूप से प्रचार 15 नवम्बर को समाप्त हो जाएगा।

हाल फिलहाल जिले में चुनावी प्रचार को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेताओं का आना जारी है। दोनों ही दलों के नेता चुनाव प्रचार के लिए जिले में पहुंच रहे है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव प्रचार को लेकर जिले के दौरे पर थे, उन्होने कार्यकार्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इधर कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वीजयसिंह भी चुनावी प्रचार के सिलसिले में जिले के दौरे पर थे। दिग्वीजयसिंह ने जिले की तीनों विधानसभाओं में चुनावी आमसभा को संबोधित भी किया था। बताते है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री 14 नवम्बर को झाबुआ आ सकते है। प्रधानमंत्री की इस रैली में 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। आलीराजपुर-झाबुआ जिले की विधानसभाओं के साथ ही धार जिले की सरदारपुर विधानसभा के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने अपने दौरे के दौरान यह जानकारी दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण सुराना ने बताया कि, झाबुआ जिले की तीन, आलीराजपुर की दो और धार जिले की सरदारपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और जनता को प्रधानमंत्री झाबुआ में संबोधित करेंगे। आयोजन गोपालपुरा हवाई पट्टी पर होगा।

विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही दल इन दिनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते नजर आ रहे है। भाजपा लाडली बहना योजना का जमकर प्रचार कर रही है तो कांग्रेस भी सरकार बनने के बाद कई योजनाओं और वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। हालांकि इन राजनीतिक रैलियों में जनता के मुद्दे बहुत ही कम सुनाई पड़ रहे है। इसके अलावा दोनों ही दल एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। इन आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है वह है नकली और असली आदिवासी का। झाबुआ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी भानू भूरिया ने अपनी नामांकन रैली के दौरान झाबुआ बस स्टेंड पर आमसभा करते हुए युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर नकली आदिवासी होने का आरोप लगाया था। यह मामला इतना गर्माया कि, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया को आदिवासी बोलने पर मजबूर होना पड़ा। बात यहीं शांत नही हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वीजयसिंह झाबुआ जिले में अपने चुनावी के दौरान पहुंचे तो उन्होने भी भीली भाषा में विक्रांत के प्रचार व पक्ष में आदिवासी भाषा में मंच से गीत गाना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि, यह नकली और असली आदिवासी की नई लड़ाई कहां तक चलती है। हालांकि चुनाव तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे लेकिन इस विधानसभा में बोया गया नकली और असली आदिवासी का बीज कहीं जिले के लिए नासूर न बन जाए।

भाजपा की ओर से इस चुनावी माहौल में किसी बड़े नेता की कोई आम सभा अब तक देखने को नही मिली है। प्रदेश स्तरीय जितने भी भाजपा के नेता जिले की विधानसभाओं के दौरे पर आए है वे सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन करते ही दिखाई पड़ रहे है। ऐसा क्यों है यह तो भाजपा संगठन ही जाने। बताने वाले तो यह भी बता रहे है कि, भाजपा संगठन इन दिनों जमीनी स्तर से गायब नजर आ रहा है। तीनों विधानसभाओं में प्रत्याशी खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रहे है। वैसे भी भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से ही मिटिंग करते नजर आ रहे है। भाजपा की ओर से कोई भी बड़ा नेता अब तक कोई आम सभा करता दिखाई नहीं दिया है।

इसके विपरीत कांग्रेस अपनी अलग रणनीति के साथ काम करती नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं से मीटिंग तो चल ही रही है साथ ही बड़े नेताओं की आमसभा भी हो रही है। हालांकि यहां यह माना जा रहा है कि, कांग्रेस जिला संगठन मजबूती के साथ मैदान में है और तीनों विधानसभाओं में संगठन प्रत्याशियों के लिए मेहनत करता नजर आ रहा है। हालांकि यहां एक बात जरूर देखी जा रही है कि, झाबुआ विधानसभा को लेकर कांग्रेसी जिला संगठन ज्यादा ताकत लगा रहा है। जिसका कारण बिलकुल साफ है कि, झाबुआ विधानसभा से युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक कांतिलाल भूरिया के पुत्र खुद मैदान में है। कांतिलाल भूरिया जिले की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा चेहरा है और वे केंद्रीय मंत्री के साथ-साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे है। इसके अलावा रतलाम-झाबुआ संसदीय सीट से कई बार सांसद भी रहे है। जिसके कारण कांतिलाल भूरिया की प्रदेश व केंद्रीय कांग्रेस संगठन में गहरी पैठ और पकड़ है। जिसकी वजह से पूरा का पूरा संगठन अपनी अधिकतर ताकत झाबुआ विधानसभा में लगा रहा है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान कांतिलाल भूरिया के कद को दिग्वीजयसिंह भी बढ़ा-चढ़ा कर बयान कर गए है। दिग्वीजयसिंह ने अपने व कांतिलाल भूरिया के संबंधों को 50 साल पुराना बताया है।

कुल मिलाकर जिले में इस बार विधानसभा चुनाव रौचक मौड़ पर है और हर राजनीतिक दल अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग अलापने में मशगूल है। दोनों ही दल जिले की विधानसभाओं को जीतने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे है। मगर यह भविष्य के गर्त में है कि ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि जनता अभी तक खामौश ही नजर आ रही है। वोटरों के चेहरे बता रहे है कि अब की बार जैसे सब कुछ सेट हो चुका है और बस अब 17 नवम्बर का इंतजार है। यह कहना हालांकि मुश्किल होगा कि वोटरों यह माईंड सेट किस तरफ का है। फिलहाल अब मतदाता पांच दिवसीय दीपोत्सव मनाने में व्यस्त हो जाएंगे और दीपावली के बाद ही यह तय करेंगे कि किसकी दीपावली और किसका दीवाला...?

फर्जी डॉक्टरों से निजात होकर मौत के घाट उतारने वाला सिलसिला कभी खत्म होगा या नहीं...?

मामलाः फर्जी झोलाछाप अजीत राय डेंटिस्ट डॉक्टर बनकर कर रहा जानलेवा इलाज

माही की गूंज, खवासा।

जिले में बांग्लादेशी व बंगाली सभी झोलाछाप डॉक्टर जानलेवा इलाज कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर मौत के घाट उतारने का यह सिलसिला शासन व प्रशासन की कार्रवाई के साथ कभी खत्म होगा या नहीं...? यह एक बड़ा सवाल है।

खानापूर्ति के साथ की जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक कार्रवाई छुटपुट जरूर चलती है लेकिन यह औपचारिक कार्रवाई के साथ इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों को संरक्षण ही दिया जाता है। जिसका नतीजा ग्रामीण अंचल के इन झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा गारंटी के साथ इलाज करने की गारंटी देकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं।

जिसका एक और उदाहरण बुधवार को खवासा में सामने आया। खवासा के कुम्हार मोहल्ले में मेडिकल के साथ फर्जी क्लीनिक खोलकर बांग्लादेशी फर्जी डॉक्टर अजीत राय अपने आप को सबसे बड़ा डेंटिस्ट डिग्री धारी डॉक्टर बताकर अन्य बीमारियों के साथ दातों का भी इलाज कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है।

बुधवार को जो मामला सामने आया है उसमें गोपाल पिता दितीया जाती नलवाया बड़ी झरिया (सागवा) 8 दिन पूर्व दातों में तकलीफ होने के चलते उपचार हेतु खवासा आया थां। कुम्हार मोहल्ले में बांग्लादेशी फर्जी झोलाछाप अजीत राय ने उक्त मरीज के दातों व जबड़े का इलाज गारंटी के साथ अच्छा कर दूंगा कहकर किया था लेकिन यह बांग्लादेशी फर्जी डॉक्टर अजीत राय ने उपचार के नाम पर उक्त मरीज को मरणा अवस्था में पहुंचा दिया।

बुधवार को गोपाल नलवाया के परिजन मरणा अवस्था में गोपाल को लेकर बांग्लादेशी फर्जी डॉक्टर अजीत राय के क्लीनिक पर पहुंचे और विवाद की स्थिति बन गई। स्थिति को बिगड़ते देख शातिर एवं ढोंगी बांग्लादेशी डॉक्टर अजीत राय ने मरीज के साथ परिजनों को विश्वास में लेने का प्रयास किया और मरीज को सुधारने में जितना भी पैसा खर्च होगा वो में करूंगा कहकर चार पहिया वाहन किराए से कर मरीज और परिजनों को उपचार करवाने हेतु रतलाम ले गया।

अब देखना यह है कि, रतलाम में मरीज का बिगड़ा हुआ स्वास्थ में सुधार होता है या नहीं, वही कुंभकरणी नींद में सोया स्वास्थ विभाग इस और कोई कार्रवाई करेगा या फिर लोगो की जान से खिलवाड़ करने वाले बांग्लादेशी डॉक्टर अजीत राय से साठ-गांठ कर पुनः ग्रामीणों का जानलेवा उपचार करने हेतु छूट दे दी जाएगी।

56 सहकारी एवं निजी फर्म से किया यूरिया का वितरण

माही की गूंज, मंदसौर। उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि, जिले में दो रैक से प्राप्त यूरिया सुचारू रूप से वितरण किया गया। मन्दसौर जिला में कुल 56 सहकारी एवं निजी फर्म से यूरिया वितरित किया गया। इसमें से जिला विपणन के 5 केंद्र, मार्केटिंग सोसायटी के 8 एम.पी. एग्रो के 02 और निजी के 41 केन्द्र से यूरिया का वितरण किया गया। समस्त केन्द्रों पर आए सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध हो गया है।

कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा अनुसार बोनी के पश्चात 21 दिन बाद प्रथम सिंचाई एवं 42 दिन बाद द्वितीय सिंचाई पर ही यूरिया का छिड़काव करना चाहिये। प्रथम सिंचाई के समय 25-30 किलो नत्रजन और द्वितीय सिंचाई के समय 25-30 किलो नत्रजन देना अनुसंशित है। 4 बीघा गेहूं में प्रथम सिंचाई के समय 2 बैग यूरिया और द्वितीय सिंचाई के समय 2 बैग यूरिया का छिड़काव करना पर्याप्त होता है। दोनो सिंचाई में कुल 4 बैग डालने के बाद यूरिया डालने से उपज में कोई फायदा नहीं होता है।

तेलिया तालाब के बहुप्रतिक्षित मामले में एनजीटी का आया आदेश

माही की गूंज, मंदसौर। जिले के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित तेलिया तालाब के मामले में मंगलवार को एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए तेलिया तालाब के मूल नक्शे के विवाद को खत्म करते हुए नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेन्सी हैदराबाद द्वारा दिए गए नक्शे को मान्य कर लिया है। इसके पूर्व तेलिया तालाब के मूल नक्शे को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि तेलिया तालाब के तीन से चार नक्शे एनजीटी के पास पहुंचे थे। लेकिन अब इस विवाद पर विराम लग गया है।

तेलिया तालाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलिया तालाब के मामले में एनजीटी को सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया था। जिसके बाद एनजीटी ने इस मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक टीम का गठन किया था। जिसमें राजस्व विभाग कलेक्टर द्वारा आरपी वर्मा, तत्कालीन अपर कलेक्टर मंदसौर, आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश मप्र द्वारा विष्णु खरे संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश उज्जैन, अध्यक्ष नगर पालिका मंदसौर द्वारा सुधीर कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर और जल संसाधन विभाग द्वारा विजयेन्द्र सिंह डोडवे कार्यपालन यंत्री को मनोनीत किया था। अब यही टीम एनजीटी के आदेशानुसार स्थल का डीमार्कनेशन कर दो माह में एनजीटी को फायनल रिपोर्ट पेश करेगी। एडव्होकेट ललित कुमार मोदी ने बताया कि, तेलिया तालाब के मूल नक्शे का विवाद खत्म हो गया है। अब आदेश के अनुसार गठित टीम को दो माह में स्थल की डिमार्कनेशन कर फाइनल रिपोर्ट एनजीटी को पेश करना है। यदि डिमार्कनेशन के दौरान कोई आपत्ति आती है तो उसका निराकरण भी गठित टीम को ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर करना होगा।

पार्टी समर्थको का दंगल बना सोशल मीडिया

तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप और तरह-तरह की वीडियो क्लिप से भरी पड़ी सोशल साईटस्

माही की गूंज, झाबुआ।

आधुनिकता की चकाचौंध में प्रदेश का यह दूसरा विधानसभा चुनाव है। देश और प्रदेश के साथ ही आदिवासी अंचल भी इंटरनेट की दुनिया से ताल ठोकते दिखाई दे रहा है, जिसमें ठेठ गांव खेड़े के लोगों ने भी संचार क्रांति में अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। क्षेत्र आदिवासी बाहुल होने के बावजूद हर हाथ तक एंड्रोईड मोबाईल की उपलब्धता आदिवासियों को विश्व भर से जोड़ रही है। इसका फायदा भी आदिवासी वर्ग अब उठाने लगा है। इंटरनेट की सस्ती उपलब्धता के चलते ऑन लाईन शॉपिंग हो, फिल्म, गाने या सोशल मीडिया के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करना इस आदिवासी अंचल ने सीख लिया। इतनी तेजी से इंटरनेट की दुनिया में उठकर आने में कहीं न कहीं आदिवासियों के पलायन का बड़ा सहयोग भी माना जा सकता है।

हाल-फिलहाल समय विधानसभा चुनावों का है और विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर खासा गरम माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के इंटरनेट से जुड़ने के बाद चुनावी प्रचार-प्रसार ने भी अपना तौर-तरीका बदल लिया। पिछले समय जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था उस समय चुनाव प्रचार का अपना ही एक अलग तरीका था जो बरसों से चला आ रहा था। पहले चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी गांव-गांव जाकर घर-घर सम्पर्क करते थे, चौपालें लगाते थे, खाटला बैठकें करते थे, पर्चे छपवा व बंटवाकर चुनावी प्रचार किया जाता था। यह कहा जा सकता है कि, बहुत ही सादगी के साथ यह प्रचार किया जाता था, किसी प्रकार की चकाचौंध चुनाव प्रचार में नहीं हुआ करती थी। वर्ष 2014 में हुए आम चुनावों में प्रत्याशीयों, पार्टियों के प्रचार का तरीका तब्दील होकर इंटर की दुनिया में पहुंचा। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार शुरू हुआ। राजनीतिक गलियारों में सोशल मीडिया के इस प्रचार ने ऐसा जोर पकड़ा कि, भाजपा और मोदी की लहर बनाकर सरकार का तख्ता पलट कर दिया।

आज की अगर बात करें तो यह आदिवासी अंचल अब पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया में गोते लगाता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया साईटस पर अकाउंट खोले जा रहे है, प्रोफाईल बनाई जा रही है, टिव्ट किए जा रहे है, आचारों-विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अंचल का कोई भी क्षेत्र इंटरनेट की दुनिया से अछूता नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 सर पर है और इन चुनावों में भी सोशल मीडिया प्रत्याशियों व पार्टियों का दंगल बना हुआ है। सोशल साईटस में फैसबुक व व्हाटस एप पर तो बहुत अधिक हंगामा मचा हुआ है। फैसबुक व व्हाटस एप पर प्रत्याशी व उनके समर्थक अपना प्रचार करने के बजाए प्रतिद्वंदियों पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे है तो नित नई विडियो, स्टेटस, कमेंटस एक-दूसरे पर किए जा रहे है। सोशल मीडिया से प्रचार को लेकर भी निर्वाचन विभाग इस बार सख्त नजर आ रहा है। प्रत्याशी को अपने से जुड़ी तमाम इंटरनेट संबंधी जानकारी जैसे ई-मेल अकांउट, फैसबुक अकाउंट, व्हाटस एप अकाउंट की पूरी जानकारी निर्वाचन विभाग को देना जरूरी कर दिया गया था। निर्वाचन विभाग प्रत्याशियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके सभी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखे हुए है। निर्वाचन विभाग की सख्ती होने के कारण कोई भी प्रत्याशी सोशल मीडिया पर इतना सक्रिय तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अपने समर्थकों के जरिए सोशल साईटस पर जमकर मुकाबला किया जा रहा है। प्रत्याशियों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं का बर्ताव सोशल मीडिया पर ऐसा होता जा रहा है जैसे वे किसी जंग में आमने-सामने है और एक-दूसरे पर वार करने को आतूर है। एक समर्थक अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई विडियो पोस्ट करता है तो दूसरा समर्थक अपने खिलाफ पोस्ट हुई विडियो के जवाब में अगले के खिलाफ विडियो पोस्ट करता है। यह सोशल मीडिया की जंग इस कदर चलती है कि, मानों चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं वरन् वह खुद लड़ रहे हों। स्टेटस और कमेंट के जरिए तीखी नोक-झोक भी सोशल साईटस पर खूब देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर चल रही इस जंग को देखते हुए कुछ लोगों ने समझाईश के तौर पर एक स्टेटस पोस्ट भी की जिसमें यह संदेश दिया गया कि श्चुनाव के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब न करें्य। समझाईश के लिए की गई इस पोस्ट का अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। हम तो नहीं मानेंगे तर्ज पर समर्थक अपनी-अपनी प्रतिद्वंदिता निभाने में लगे हुए है। निर्वाचन विभाग प्रत्याशियों व उनके अकाउंट, आईडी पर तो नजर रखे हुए लेकिन समर्थकों व कार्यकर्ताओं पर किसी प्रकार को कोई दबाव नहीं है। बस इसी के चलते इन दिनों सोशल मीडिया पार्टियों व प्रत्याशियों का दंगल बना हुआ है।

नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं कर रही पुलिस, परिजन परेशान

नाबालिगों के लिए बने कानून का मजाक बनाती पुलिस

माही की गूंज, पेटलावद।

जिले में चल रही भांझगड़ी प्रथा अब इस कदर हावी हो चुकी हैं कि, नाबालिग बच्चों के साथ खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ घटित अपराधों को लेकर भी पुलिस अपराध दर्ज करने की बजाए, आपसी सुलह सहमति होने तक इंतजार करती हैं और कई बार पुलिस की लापरवाही के कारण मासूम बच्चों को किसी बड़े अपराध का शिकार हो जाते हैं।

मामला पेटलावद थाना क्षेत्र की करवड़ चौकी का है जहा वरसिंह निवासी खाखरापाडा की नाबालिक पुत्री शारदा (बदला हुआ नाम) उम्र 15 वर्ष की जो लगभग दो माह से घर से गायब है। नाबालिक के पिता ने बताया कि, पुत्री के घर से गायब होने के बाद मेरे द्वारा मेरी पुत्री का परिवार और रिश्तेदारों ने काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई अता-पता नही लगा और जो लोग हमारे यहा से मजदुरी के लिये गये थे उनसे पुछताछ करने पर भी लडकी नही मिली। जिसके बाद पता चला कि, मेरी पुत्री को विपक्षी देवीलाल पिता हरिराम सिंगाड निवासी दंतोडा जिला रतलाम जबरन अपहरण कर ले गया है। जिसकी रिर्पोट मेरे द्वारा 8 अक्टुबर 2023 को चौकी करवड में दी थी।

नहीं किया अपराध दर्ज, लड़की को ले जाने वाले परिवार को बुलाकर मामला कर दिया रफा-दफा

नाबालिको के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर गम्भीर सरकार ने कड़े कानून बना रखे है, 24 घंटे में किसी भी स्थिति में मामला दर्ज करना होता है लेकिन करवड चौकी प्रभारी ने अपहरण और गुमशुदगी का अपराध दर्ज करने की बजाये लड़की को ले जाने वाले परिवार की खोजबीन कर उसके परिवार को चौकी पर बुलाया वही बिना अपराध दर्ज के ही चौकी में आये आरोपितो के परिजनो के लड़की लाने के झुठे आश्वासन पर पुलिस ने आरोपितो के परिजनो को छोड़ दिया। जो पुलिस को झासा देकर लापता हो गये।

नाबालिग लड़की का आधार कार्ड

थाने पर भेजा रिपोर्ट के लिए, थाने वालो ने भगा दिया

करवड चौकी को 5 दिन का कहने के बाद जब आरोपी पक्ष बीस दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नाबालिक को लेकर नही आये। तो नाबालिग के पिता द्वारा करवड चौकी पर सम्पर्क किया, तो करवड चौकी से उसे थाना पेटलावद भेजा गया जहा फरियादी की रिर्पोट नही लिखी और कहा कि, करवड चौकी से पुलिस आकर, हेडसाब से तुम्हारी कायमी करवायेगी। मंगलवार को पीड़ित पिता जब दोबारा थाने पहुँचा तो थाना पेटलावद पर उपस्थित पुलिस द्वारा रिर्पोट लिखने से मना कर रवाना कर दिया। नाबालिक के पिता ने बताया कि, इस संबंध में एसडीओपी पेटलावद को लिखित शिकायत की है और यहां से कोई कार्रवाई नही होती है पुलिस अधीक्षक को शिकायत करूंगा।

लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं नाबालिग

आदिवासी अंचल से गायब होने वाली लड़कियों के गायब होने पर पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर कानून को ताक में रखकर कोई कार्रवाई नही करती। कई बार मामले आपसी रजामंदी से खत्म हो जाते हैं तो कई बार ऐसे मामलों में नाबालिग अपराध का शिकार हो जाती है। पुलिस आरोपी पक्ष में मामला निपटाकर पीड़ित पक्ष में कोई कार्रवाई नही करती हैं जो नाबालिग अपराध को लेकर चिंता का विषय बनता जा रहा है।

निर्दलीय बिगाड़ सकते है बागियों का खेल

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पांचाल

इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर जोरो से तैयारी चल रही है गांव-गांव जाकर उम्मीद्वार बैठक कर रहे है और दोनों ही प्रमुख दलों के नेता अपनी-आपनी सरकार में किए गए, कार्यों को बढ़-चढ़कर बता रहे हैं। वही निर्दलीय उम्मीद्वार भाजपा एवं कांग्रेस इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सरकार को रहते जमकर हुई भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 17 नवंबर को मतदान होना है और महज एक सप्ताह रह गया है और दोनों ही प्रमुख दलों का प्रचार-प्रसार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बैठकों के अलावा ना कहीं झंडा नजर आ रहे हैं और ना कहीं बैनर दिख रहे हैं और ना ही प्रचार-प्रसार के वाहन नजर आ रहे हैं। विधानसभा के क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है जहां दो प्रमुख पार्टियों के अलावा भाजपा के ही वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व जनपद अध्यक्ष ने भाजपा के प्रत्याशी कलसिंह भाबर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और निर्दलीय को समर्थन देकर उनके पक्ष में मतदान करवाने के लिए जोर-जोर से प्रचार-प्रसार चल रहा हैं। निश्चित ही यह भाजपा के लिए नुकसानदायक होकर कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। वही क्षेत्र में चर्चा है कि, दिलीप कटारा कांग्रेस के समर्थन में भी अपनी भुमिका अंदरखाने निभा रहे है। इस क्षेत्र में कांग्रेस में भीतर घात करने वाले खुलकर अभी कोई सामने नहीं आया है। जिससे कयास यह लगाया जा रहा है कि, निश्चित ही भाजपा का खेल निर्दलीय बिगाड़ सकता है।

आबकारी पुलिस ने जप्त की अवैध शराब

माही की गूंज, थांदला। आबकारी पुलिस थांदला की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम चापानेर में दिनेश पिता विसिया डामोर के मकान में दबिश देकर 3 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों में कुल 130 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब जप्त की। जिसकी अनुमानित कीमत 26 हजार रुपये है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर थांदला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहा से आरोपी को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल सिंगाड़ा के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई जिसमें मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर, आरक्षक मोहन नायक, अर्जुन सिंह नायक, भारती का सराहनीय योगदान रहा।

कर्मचारियों का वोट आखिर किधर...?

माही की गूंज, पेटलावद।

विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ अलग करते हुवे 80 से अधिक उम्र वाले मतदाता जो बूथ पर मतदान के लिए नही जा सकते उनके लिए घर पहुँच सेवा कर मतदान करवाने की व्यवस्था की। पेटलावद विधानसभा के लिए लगभग 39 मत अस्सी प्लस के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वही जिन शासकीय कर्मचारियों का मतदान भी सम्पन्न हुआ जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है या चुनाव ड्यूटी की सूची में नाम है। कर्मचारियों के मतदान के बाद कई कर्मचारियों से मतदान को लेकर हुई चर्चा में रोचक तथ्य सामने आया। कर्मचारी अधिकांश सरकार का वोटर माना जाता रहा है लेकिन इस बार जो रुझान मिल रहे हैं उससे वोट बैंक तीन हिस्सों में बटता दिख रहा है। मतलब किसी भी एक दल के पक्ष में मतदान नही हुआ है। इस बार पुरानी पेंशन लागू करने का मुद्दा हावी रहा और पुरानी पेंशन लागू करने के वादे ने कर्मचारियों को आकर्षित किया। तो साथ ही नई पीढ़ी का कर्मचारी दोनों दलों से अलग नई सोच की ओर झुकता दिखा। वही पुराना कर्मचारी जो सरकारी सभी योजनाओं का लाभ ले रहा है वो सत्ता के साथ जाता दिखाई दिया। कुल मिलाकर इस बार कर्मचारियों का मत किसी एक दल का वोट बैंक होने की बजाये अपने-अपने मुद्दे सहित क्षेत्र की राजनीति से प्राभवित दिखाई दिया। वसुली और ट्रांसफर के नाम पर प्रताड़ित कर्मचारी पुरी तरह से नाराज होकर वोट करता दिखा। हमारी राजनीतिक चटपटी खबर यही बता रही है कि, इस बार चुनाव में भाजपा को कर्मचारियों का समर्थन पूर्व की तरह नही मिलता दिख रहा है।

आखिरकार कब जागेगा एमपीआरडीसी विभाग...?

माही की गूंज, सारंगी।

पिछले कई दिनों से थांदला-बदनावर हाइवे रोड़ पर स्थित टेमरीया पेट्रोल पंप के पास रोड़ के बिचोबिच बड़ा गड्ढा हो गया है, और इस गड्ढे के कारण अब तक कई वाहन एक-दूसरे से टकराते रहें हैं लेकीन क्या इस रोड से संबंधित विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद जागेगी...? और उसके बाद इस रोड़ पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत की जाएंगी या किसी परिवार के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद विभाग जागेगा ओर रोड़ का रिपेयर करवाया जाएगा। मार्ग पर कई जगहों पर स्थिति इतनी गम्भीर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

श्रीसंघ ने गुरु दर्शन यात्रा निकालते हुए किये गुरु दर्शन

माही की गूंज, थांदला।

श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी श्रावक संघ थांदला के अध्यक्ष भरत भंसाली के नेतृत्व में संघ व पूज्य श्री धर्मलता महिला मंडल, अणु जिनेन्द्र बालिका मण्डल एवं श्री महावीर जैन पाठधाल के 40 से अधिक सदस्यों ने धार में विराजित रोचक वक्ता पूज्य श्री संदीपमुनिजी म.सा. आदि सन्तों के दर्शन वंदन एवं प्रवचन का लाभ लिया व वार्षिक क्षमापना करते हुए थांदला पधारने की विनंती की। पूज्य श्री ने धर्म सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, बड़ो की नजर ही दौलत है, अतः पारिवारिक संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए छोटों को बड़ो की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पूज्य श्री ने बालिकाओं को धर्म सन्देश देते हुए कहा कि, आधुनिकता कि होड़ में रहन-सहन, पहनावे व खान-पान में जो विकृतियां आई है वह चिंता जनक है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्हें सत्संग एवं बड़ो की आज्ञा का अनुसरण करने की परम आवश्यकता है। धर्मसभा में पूज्य श्री चन्द्रेशमुनिजी म.सा. ने भगवान की अंतिम देशना उत्तराध्ययन के सम्यक्त्व पराक्रम के 46वें बोल का विवेचन किया। इस दौरान पूज्य श्री ने थांदला संघ अध्यक्ष भरत भंसाली द्वारा संघ रूप में की गई विनंती पर कहा कि, यथा समय थांदला स्पर्शना के भाव है। बालिका मण्डल ने भी स्तवन के माध्यम से अपनी विनती रखी। सभा का संचालन वरिष्ठ स्वाध्यायी रमेश ओस्तवाल ने किया।

बीएलओ घर-घर जाकर दे रहे मतदान पर्ची के साथ जानकारी

माही की गूंज, थांदला।

विधासभा चुनाव में मतदान की तारीख 17 नवम्बर जैसे-जैसे समीप आ रही है प्रत्याशियों का जनसम्पर्क भी दुगुना उत्साह व वेग से चलने लगा है। इस बीच प्रशासन भी बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं तक जाकर मतदान करने की अपील करते हुए आवश्यक जानकारी भी दे रहे है। थांदला विधानसभा 194 वार्ड क्रमांक-2 के बीएलओ प्रभु कटारा ने घर-घर जाकर मतदान पर्ची का वितरण करते हुए राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग करते हुए मतदान करने की समझाइश देते हुए आवश्यक जानकारी भी दे रहे है। प्रभू ने बताया कि, इस बार मतदान पर्ची के साथ आधार, वोटर आईडी अथवा अन्य पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पर्ची में भी उक्त निर्देश दिए गए है। वही प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा, जो सायं 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान मतदान केंद्र पर आने वालें सभी मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार होगा। मतदान स्थल पर महिलाओं के लिए अलग कतार रहेगी, वही वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता दी जाती है। नेत्रहीन और अशक्त मतदाता को मतदान करने के लिए वयस्क साथी को मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति भी रहेगी। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा जैसे उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। निर्वाचन अधिकारी तरुण जैन ने कहा कि, मतदान स्थल पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त जल व अन्य सुविधाएं भी रहेगी। उन्होंनें सख्त निर्देश देते हुए बताया कि, किसी विशेष उम्मीद्वार के पक्ष में वोट देने के लिए धन या कोई अन्य लाभ की पेशकश करना या स्वीकार करना कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है जिसके लिए सजा का प्रावधान है।

बीएलओ द्वारा वितरित पर्ची मतदान के लिए है अवैध

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, मतदान म पारदर्शिता लाने व फर्जी अवैध मतदान रोकने के लिए बीएलओ द्वारा दी जाने वाली पर्ची केवल मतदान जागरूकता व उनकी सुविधाओं के लिए वितरित करवाई जा रही है। वही पर्ची में ही सभी तरह के निर्देश करते हुए मतदान की जानकारी दी जा रही है। लेकिन यह पर्ची मतदान केंद्र पर पहचान के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको मतदान के लिए मतदाता का पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को ले जाना अनिवार्य होगा।

समूह की महिलाओ द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए शपथ दिलाई

माही की गूंज झाबुआ।

जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राणापुर में महिला मतदान जागरूकता बढ़ाने एवं महिलाओं को शतप्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे समूह की महिलाओ को आगामी 17 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम में समूह की सदस्य धामनी कटारा द्वारा बताया गया कि, लोकतंत्र में सभी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। उसकी सबसे बुनियादी प्रक्रिया है मतदान। इसलिए मतदान के प्रति जागरूक होना हम सबका क?र्त्तव्य है। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव न करें। ऐसे प्रतिनिधि को वोट करना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करे।

आत्म रक्षा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र व ट्रेक सूट किये वितरित

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला प्रशासन झाबुआ, मध्य प्रदेश टूरीज्म बोर्ड एवं वसुधा विकास संस्थान द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत संकुल झाबुआ के पर्यटन स्थल झाबुआ के शारदा विद्या मंदिर स्कूल एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलवार को 60 दिवस की ट्रेनिंग पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र एवं ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के दौरान जो टिप्स सीखे उसका डेमो की प्रस्तुति दी एवं आत्म रक्षा ट्रेनिंग के पूर्व एव ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद छात्राओं में आत्मविश्वास सकारात्मक बदलाव देखा उसके विषय में विस्तार से छात्राओं ने अनुभव साझा किए।

वसुधा विकास संस्थान से सुश्री डॉ.गायत्री परिहार (डायरेक्टर) ने कहा कि, बालिकाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर था, जहाँ वे अपने निकट इस तरह का प्रशिक्षण लिया, जो अब भविष्य में उन्हें

किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी अवांछित घटना से बचने में सहायक होगा। परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से परियोजना काल में पर्यटन स्थल की 800 लड़कियों को आत्म सुरक्षा का निशुल्क प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इसी क्रम में अभी तक झाबुआ की 636 बालिकाओं को 60 दिवसीय आत्म रक्षा प्रशिक्षण पूर्ण हो चूका हैं, जिसमे बालिकाओं को किसी भी आकस्मिक स्थिति में स्वयं की रक्षा करने की तकनीकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को साइबर क्राइम, इन्टरनेट सेफ्टी, महिला हेल्प लाइन, महिला डेस्क, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में जागरूक करने के लिए सत्र आयोजित किये गए व आगे भी सत्र आयोजित किये जायेगे।

पुलिस डिपार्मेंट से सुश्री ममता एवं श्रीमती संतोष (महिला आरक्षक) ने कहा कि, मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की यह बहुत ही अनूठी पहल है, छात्राओं द्वारा आत्म रक्षा प्रशिक्षण डेमो देखने के बाद मै कह सकती हूँ कि, छात्राओं में वह आत्मविश्वास दिख रहा है कि, अब वह खुद की सुरक्षा कर सकती है साथ ही दूसरी महिला की भी रक्षा कर सकती है, साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकरी दी।

संपादकीय

राज्य सरकार व पंजाब के बीच अनावश्यक टकराव

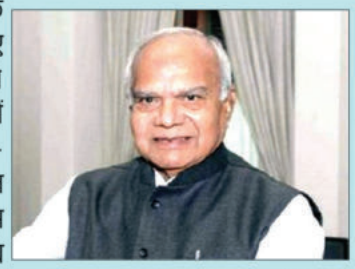

हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में राज्य सरकारों व राज्यपालों के बीच गहरे टकराव के मामले प्रकाश में आए हैं। विडंबना यह है कि ये मामले उन राज्यों में सामने आए जहां गैर-राजग सरकारें कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व तमिलनाडु के बाद हालिया विवाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार व पंजाब के राज्यपाल के बीच है। यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राज्यपालों को आत्मावलोकन करना चाहिए। जाहिर है विसंगतियों के हालात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस गरिमामय संवैधानिक पद के अनुरूप गरिमामय टिप्पणी ही की है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामले अदालत में पहुंचें उससे पहले राज्यपाल को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब में लंबे समय से भगवंत मान सरकार व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव चला आ रहा था। दरअसल, राज्यपाल ने तीन धन विधेयकों को मंजूरी देने से मना कर दिया था। हालांकि, बाद में एक नवंबर को दो विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले भी राज्यपाल ने पिछले महीने बुलाए गये पंजाब विधानसभा के सत्र को अवैध तक बता दिया था। इस मामले में शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यपालों को मामला कोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। यह परिपाटी खत्म होनी चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट आने पर राज्यपाल कार्रवाई करेंगे। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने राज्यपालों को आत्मावलोकन की जरूरत बताते हुए नसीहत दी कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। जाहिर है कि कोर्ट का सीधा अभिप्राय: है कि माननीय कहे जाने वाले राज्यपाल पद की मर्यादा के अनुरूप ही व्यवहार करें। विडंबना ही है कि हाल के वर्षों में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते देखे गए हैं।

नि:संदेह, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिये विडंबना ही कही जाएगी कि राज्यपाल किसी राज्य सरकार के कार्यों में बाधा डालें व कैबिनेट के फैसलों को अनुमति देने में आनाकानी करें। राज्यपाल का काम किसी भी राज्य को किसी भी तरह के संवैधानिक संकट से ही बचाना होता है। वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं ताकि राज्य के विकास के कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सकें। मगर यदि वे सरकार बनाने व गिराने के खेल में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से राज्यपाल के पद को आंच आएगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक विद्रूपताओं के चलते उत्पन्न अस्थिरता के दौर में राज्यपाल की भूमिका को लेकर तीखे सवाल उठे और मामला शीर्ष अदालत तक भी पहुंचा था। ऐसा ही टकराव पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के शासन के दौरान भी नजर आया था। विडंबना यही है कि राज्यपाल के पद पर समाज के विद्वानों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करने के बजाय रिटायर राजनेताओं को बैठाने का खेल दशकों से जारी है। इस खेल में भाजपा से लेकर कांग्रेस तक कभी पीछे नहीं रहे। जिसके चलते वे पद पर बैठते ही अपने पर 'कृपा करने वाले दल' की निष्ठाओं को निभाने के लिये संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करने लगते हैं। फिर चुनी हुई सरकार से टकराव की खबरें सूचना माध्यमों में तैरने लगती हैं। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं किसी भी लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं कही जा सकतीं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के राज्यपाल की ओर से शीर्ष अदालत में उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि राज्यपाल ने उनके पास भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई की थी। साथ ही यह भी कि पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका एक अनावश्यक मुकदमा है। बहरहाल, राज्यों व केंद्र सरकारों के मध्य एक पुल का काम करने वाले राज्यपाल को राज्य के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही जनता द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को संबल देना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र राज्यपालों से नीर-क्षीर विवेक के साथ दायित्व निभाने की अपेक्षा करता है।

आम चुनाव की दिशा प्रभावित करेंगे नतीजे!

के.एस.तोमर

इस बात में शायद ही कोई संशय हो कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत के लिए पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर निर्भर हो गये हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के मतदाताओं के नाम जारी अपील है। वहीं भाजपा हाईकमान द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री और अन्य दावेदारों को नजरअंदाज कर किसी को भी आगामी मुख्यमंत्री के रूप में पेश न करने से लगता है कि शिवराज सिंह को पूरी तरह पीछे कर दिया गया है।

वहीं इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर अलग-अलग राय है। एक पक्ष का मानना है कि इनमें हार-जीत का लोकसभा चुनाव के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रांतीय और देश के चुनावों में मतदाताओं की सोच अलग-अलग होती है। पिछले बार हिन्दी क्षेत्र के राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हारने के बावजूद 2019 में भाजपा ने लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की थी और मध्यप्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की 25 में से 24 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीती थीं। अब यदि ये विधानसभा चुनाव भाजपा जीतती है तो लोकसभा चुनावों पर दोहरा असर होगा जिसके परिणामस्वरूप मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय होगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उच्च स्तर पर है और देश में मतदाताओं में भी पकड़ मजबूत है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा को हिन्दुत्व एजेंडे का बहुत सहारा मिलेगा। चुनावों से पहले अयोध्या में राम मंदिर का जनवरी में निर्माण पूरा होने का लाभ भी पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा भाजपा के पास साधनों की कमी नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी पूरी तरह सक्रिय

होगा। भाजपा मतदाताओं को यह समझाने का प्रयास करेगी कि एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम किया है जिसे आगे भी जारी रखना जरूरी है क्योंकि इसी नेतृत्व के तहत धारा 370 को हटाना और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण बिल पास करना संभव हो सका।

इसके विपरीत पक्ष के लोग यानी भाजपा के आलोचक मानते हैं कि यदि पार्टी विधानसभा चुनाव हारी तो इसका प्रतिकूल असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। उनका कहना है कि इस समय कई ऐसे कारण हैं जो भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। पहला यह कि अब कोई प्रकरण होने की संभावना नहीं है जिससे देश में राष्ट्रवाद की लहर बने। दूसरे, 2019 में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की साख निरंतर गिर रही थी और देश के सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वहीं अब मोदी का करिश्मा इतना सशक्त नहीं कि वह भाजपा के 9 वर्ष के शासन के प्रति निराशा को पूरी तरह नकार सके। चौथी बात, महंगाई से परेशान आम आदमी में निराशा है। यह भी कि रोजगार संबंधी वादों को पूरा न करने के कारण युवा वर्ग नाराज है। वहीं दक्षिणी राज्यों में भाजपा के विजय रथ को कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत दर्ज कर रोका तो अन्नाद्रमुक ने भाजपा से गठबंधन तोड़ पार्टी को बड़ा झटका दिया है। यदि भाजपा और इसकी सहयोगी पार्टियां दक्षिण से सम्मानजनक सीटें नहीं जीतीं तो पार्टी का 2024 में सत्ता में लौटना मुश्किल होगा।

देश के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। यदि इस गठबंधन के घटक सीटों पर समझौता करने में सफल रहे तो भाजपा की राह आसान नहीं होगी।

मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर रणनीति के चलते भाजपा हाईकमान ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल आदि सांसदों के नाम पहली सूची में ही शामिल किये थे। पार्टी की सोच है कि केंद्रीय मंत्रियों का अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद विधानसभा चुनावों की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होते जो मध्य प्रदेश में घाटे का सौदा बन सकता है। हालांकि भाजपा ने शिवराज चौहान को मैदान में उतारा है।

नयी रणनीति के अनुसार इस बार भाजपा ने विधानसभा चुनावों में जीत के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित 24 सांसदों को मैदान में उतारा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सही माहौल बनाया जा सके। बात पुराने के स्थान पर नए चेहरे भी उतारने की हो तो यह प्रयोग उत्तराखंड, गोवा में तो सफल रहा लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में असफल रहा।

वहीं हिमाचल और कर्नाटक में प्रधानमंत्री द्वारा धुआंधार प्रचार और हिन्दुत्व के सहारे के बावजूद भाजपा को शिकस्त मिली थी। इसके अलावा यदि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) भी कांग्रेस के विजय रथ को नहीं रोक पाती तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है तो मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा।

मुफ्त का चंदन

डॉ. शशि तिवारी

मुफ्त की चीजें किसे अच्छी नहीं लगती, अधिकांश लोगों का उत्तर होगा हां सभी को कुछ अपवादों को छोड़। इस प्रथा से एक आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती हैं। व्यक्ति में नाकारापन की प्रवृत्ति भी जन्म लेने लगती हैं। आजकल सरकारे चावर्क के सिद्धांत अर्थात् जब तक मानव जीवन है तब तक सुख के साथ जीना चाहिए। भले ही इसके लिए दूसरों से ऋण लेकर भी घी पीना संभव हो तो निःसंकोच पीना चाहिये। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों के मध्य चुनावी रेवड़ियों की एक प्रतिस्पर्धा सी चल निकली है बिना इसकी परवाह किये कि, राजकोष की स्थिति क्या हैं? राजनीतिक पार्टियों का एक ही फार्मूला रहता है कि, अगर जीते तो टैक्स बढायेंगे ओर हारे तो दाव खेला। वर्तमान में महंगाई बढ़ने का यह भी एक कारण हो सकता है। इस ओर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान नहीं है। यहां यक्ष प्रश्न उठता है कि, चुनावी मौसम में ही ''फ्री कल्चर'' की भरमार क्यों? वास्तव में सरकार को निष्पक्ष रूप से ऐसी योजनायें चलानी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने। फ्री कल्चर सिर्फ और सिर्फ नाकारा बना सकता है, एवं कालांतर में यही ''फ्री कल्चर'' कहीं अधिकार न बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।

वास्तव में हमारा देश/प्रदेश जनता के ही टैक्स के पैसों से चलता है फिर विकास या ''फ्री कल्चर'' में सरकारे जनता की सहमति क्यों नहीं लेती? वास्तव में टैक्स के पैसों को खर्च करने की जवाबदेही अफसरों की होती हैं? वास्तव में पैसों का दुरूपयोग होने पर इन अफसरों पर जवाबदेही तय होना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके है कि, नाकारा एवं भ्रष्ट अफसरों की एक सूची तैयार की जावें। आज अफसर भी नेताओं जैसे वक्तव्य देने लगे है मसलन हम देख रहे हैं, जांच चल रही है, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जायेगा आदि, आदि। यहां भी अफसरों की जवाबदेही तय हो कार्यवाही होना चाहिये।

वर्तमान में ऋण लेने की सीमा जी.डी.पी. का 5.9 प्रतिशत केन्द्र सरकार के लिए एवं राज्यों के लिए 3 प्रतिशत है। राज्यों के जी.एस.डी.पी. की तुलना में कर्ज की स्थिति राजस्थान (15.7) कर्ज, 36.8 प्रतिशत मध्यप्रदेश (12.87), 30.4 प्रतिशत तेलंगाना (14) 23.8 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ (5.07) 23.8 प्रतिशत इस तरह राज्यों का सीमा से ज्यादा बढ़ता कर्ज और इसी तरह कर्ज लेने की प्रवृत्ति रही तो इन राज्यों का भविष्य ठीक नहीं हैं। यहां अधिकारियों को भी सरकार को सही/गलत के बारे में नोटशीट पर अवगत कराते रहना चाहिए एवं दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिये। आम जनता को भी ये जानने का हक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने पहले से ही दे रखा है। ऐसे दोषी अधिकारियों को भी दण्डित किया जाना चाहिए।

आर. बी. आई. की 31 मार्च 2023 तक की रिर्पोट में यह बात निकलकर आई है कि, म.प्र.राजस्थान, पंजाब एवं बंगाल जैसे राज्य टैक्स के कुल कमाई का 35 प्रतिशत तक का हिस्सा ''फ्री'' योजनाओं पर खर्च करते हैं। एक रिर्पोट के अनुसार म.प्र. राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ विगत 7 सालों में 1.39 लाख करोड़ की ''फ्रीबीज'' दी या घोषणाएं की।

म.प्र. में चलने वाली फ्री योजनाओं में मुख्यतः लाड़ली बहना योजना उसमें 1000 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 1250 रूपये इसे भी बढ़ाकर 3000 रूपये करने का सरकार का वादा है। लाड़ली बहना आवास योजना जिसमें आवास विहिन को आवास देना तीसरा मुख्यमंत्री हवाई तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 6000 रूपये देने की बात, ब्याज भुगतान इसमें किसानों का कर्जा सरकार भरेगी, महिलाओं के लिए सरकार गैस सिलेण्डर आदि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को मिलने वाले आयकर की कुल राशि का केवल 5 प्रतिशत लोग ही भर रहे है। यहां यक्ष प्रश्न सरकार से उठता है कि, ये सब फ्रीबीज जनता की गाढ़ी कमाई से होता है तो फिर टैक्स पेयर से क्यों नहीं पूछा जाता हैं? इस देश में टैक्स पेयर को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है जो कि, प्राथमिकता के आधार पर होना ही चाहिये। टैक्स पेयर में भी असंतोष का बीज पनप रहा है।

यही कारण है कि, टैक्स चोरी की घटनाएं एवं काला धन भी बढ़ रहा है। पड़ने वाले छापे इसका सबूत हैं, जहां-जहां जिस-जिस पर भी छापा पड़ा अकूत धन की बरामदगी हुई फिर चाहे वह नौकरशाह हो, नेता हो, व्यापारी हो या इनके गठजोड़ का ठेकेदार हो।

यहां सबसे दु:खद पहलू यह है कि, कोई भी राजनीतिक दल फ्री बीज में पीछे रहना नहीं चाहता। इस संबंध में सभी आशा भरी नजरों से न्यायालय की ओर देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने म.प्र. एवं राजस्थान में विधानसभाओं से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों सरकारों से सवाल पूछा है, प्रधान न्यायाधीश जे.बी.बाई, चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.वी.पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने सावर्जनिक धन के दुरूपयोग से जुड़ी जनहित याचिका पर केन्द्र निर्वाचन आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है।

वास्तव में आई. पी. सी. की धारा 171 बी एवं 171 सी के अनुसार मुफ्त बांटना एक रिश्वत हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि, फ्री बीज योजनाओं को रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह राजनीतिक पार्टियों का अपना नीतिगत फैसला होता है। जब तक इस संबंध में कोई नियम नहीं बन जाता तब तक इन पर कार्यवाही करना चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं है। वास्तव में न्यायालय ही तय करें कि, फ्री बीज/योजनाओं की परिभाषा क्या हैं?

सेल उत्सव में भ्रमजाल के खेल

उत्सवों के दिनों में दिल सेलों के भार से इतने दब जाते हैं, जैसे वसंत आने पर फूलों से पेड़ झुक जाते हैं। तब अखबार वाले को हमारी बालकनी में अखबार फेंकने को पूरा जोर लगाना पड़ता है। कल कह रहा था कि वह दिवाली तक अखबार गेट के बाहर ही रखा करेगा। बालकनी में अखबार फेंकते हुए उसकी बाजू में दर्द हो रहा है।

आजकल सुबह जैसे ही अखबार आता है तो हम दोनों में अखबार को लेकर जोर-आजमाइश होती है। श्रीमती अखबार में नए-नए प्रॉडक्ट के विज्ञापन जी भर निहारना चाहती है तो मैं रोज की तरह आज का ताजा राशिफल। यह दूसरी बात है कि राशि के फल के हिसाब से मुझे फल आज तक नहीं मिला। पर चलो, इस बहाने दो पल को ही सही, मन प्रसन्न हो जाता है। सारे दिन की भाग-दौड़ की जिंदगी से शुभ राशिफल के दो सुखद काल्पनिक पल बहुत अच्छे होते हैं। और तब मैं अखबार पहले पाने की लड़ाई में हर बार की तरह फिर न चाहते हुए भी हार जाता हूं।

गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद से ही गृहस्थी में हर गेम हारना मेरी नियति है या मेरा स्वभाव, मुझे कुछ मालूम नहीं। पर इस हार का एक बहुत बड़ा फायदा है, और वह यह कि घर हर लेबल के कलह क्लेशों से बचा रहता है। एक शांतिप्रिय पति को इससे अधिक गृहस्थी से और चाहिए भी क्या? जो अपनी गृहलक्ष्मी से परेशान हों उनके लिए मेरी मुफ्त की सलाह कि वे जानबूझ कर अपनी बेगम से बात-बात पर हारते रहें। घर और मन दोनों बहुत शांत रहेंगे। गृहस्थी की जंग में जो मजा पति के हारने में है वैसा मजा दीपावली के रोज जुए में जीतने में भी नहीं। अखबार में फिर विज्ञापन छपा था- अबके दीपावली है बहुत विशेष, कोई खरीदारी न छोड़ें शेष। भैया जी! इस विशेष के चक्कर में पड़ बीवी ने बाजार जाकर आज तक कुछ छोड़ा है क्या जो अबके छोड़ेगी? अब और खरीदारी करवा के शरीफ हसबेंड का और बैंड बजवाओगे क्या? चार-चार क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट थी, उस सबकी सीमा तो बाजार के बहकावे में आकर दीपावली से पहले ही बीवी वैतरणी की तरह लंघवा चुकी है। बीवी शॉप-शॉप उत्सव की दुहाई देते मेरा हौसला बढ़ाती है। मुझे बाजारू ज्ञान देती मेरी बोझ से झुकी पीठ को थपथपाती है। सोचता हूं कि इस दीपावली की खरीदारी में क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंकों का डिफाल्टर हो जाऊं तो दीपावली का मजा ही कुछ और हो। देश के बैंकों को करोड़ों की चपत लगा डिफाल्टरों का आमजन के लिए उपदेश है कि देश में जो मजा डिफाल्टर होने में है, वह अपनी जेब के हिसाब में उत्सव मनाने, पहनने, खाने में कहां?

लेखक:- अशोक गौतम

भूटान पर चीनी कुदृष्टि को समझे भारत

नमकू चो घाटी में ढोला चौकी पर चीनी हमले में मिली शिकस्त और अक्तूबर, 1962 में चीनी तानाशाह माओ ज़िदोंग द्वारा भारत को नीचा दिखाना याद है? ढोला क्षेत्र एक तरह से भारत, भूटान और चीन के कब्जे वाले तिब्बत का त्रि-संगम स्थल है। चीनी सेना द्वारा डोकलाम में किया अतिक्रमण याद है? डोकलाम भी भूटान-भारत-तिब्बत का एक त्रि-संगम है। फिर जून, 2020 में गलवान घाटी में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जन्मदिन के रोज़, चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीयों को शहीद करने वाला कुकृत्य याद है? पिछले संदर्भ में देखें तो, क्या भारत को मई, 1967 में नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल) में हुई पहली गोलीबारी याद है, जिसमें कई सिपाही मारे गए थे और यह भारत में चीनी मूल के 'जन-स्वतंत्रता युद्ध' की शुरुआत थी। चीन की साम्यवादी पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वय द्वारा बनाई और महारत से क्रियान्वित की गई यह लड़ाई, जिसके पैदल सिपाही स्थानीय कारकुन थे, 20 लंबे सालों तक अराजकता पैदा करने के बावजूद ज्यादा परिणाम नहीं दे पाई, परंतु इसमें लगभग 50000 जानों की हानि और सीमांत बंगाल सूबे के सभी प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू बर्बाद होने के अलावा क्या मिला?

भारतीय मीडिया के केवल एक हिस्से ने पिछले महीने भूटान-चीन के बीच हुई वार्ता पर खबरें कीं। पिछले सप्ताह भूटान नरेश की भारत यात्रा शुरू होने से पहले, हांगकांग की 'साऊथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' अखबार ने चीन की ओर भूटान के चिंताजनक झुकाव को लेकर चेताया है। यहां तक कि लेख में भारत को छिपी चेतावनी दी गई है कि भूटान का यह कूटनीतिक कदम क्षेत्रीय राजनयिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अखबार का यह आकलन एकदम सही है। तेजी से बदली दृश्यावली ने भारतीय प्रतिष्ठानों में खतरे की घंटी बजा डाली। वह निष्ठुर एवं खून के प्यासे ड्रैगन के खून के पंजों की पकड़ भूटान पर बनते देख अंदर तक हिल गया हैदृ यह मंज़र 1950 में आज़ाद तिब्बत पर चीनी कब्जे से पहली बने हालात की याद दिलाता है। 73 साल गुज़र गए लेकिन लोगबाग अभी भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चीन की शैतानी चालों को सफल होने देने और भारत की मुसीबतों के लिए मुख्य खलनायक मानते हैं। भारत ने अपना इलाका गंवाया है और आज भी गंवा रहा है। इस तरह अपनी संप्रभुता पर चोट पहुंचाने वाले हमलों का सामना कर रहा है।

इस चिंतनीय खबर के बावजूद चीन-भूटान के बीच बनती घनिष्ठता पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया नपी-तुली रही और 'तथ्यात्मक' बयान आया-'भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे रिश्ते हैं, जो आपसी समझ और विश्वास पर टिके हैं।' माना यह सही है, लेकिन आज के दिन वह समय-सिद्ध भारत-भूटान मित्रता और आपसी समझ एवं सहयोग पर टिके उस परस्पर विश्वास पर चीनी चालों से गंभीर खतरा आसन्न है। कदाचित यह स्थिति सदा के लिए बदल जाए।

शी जिनपिंग बाजिद हैं कि भूटान की विदेश-नीति निर्धारण में भारत की भूमिका को दरकिनार करके, चीन उसका उसका राजनयिक-दिशानिर्देशक बन जाए। सामान्य वक्त में, किसी को इस पर आपत्ति न होती। लेकिन भारत-चीन के बीच राजनीतिक-कूटनीति द्विपक्षीय संबंधों ने कभी भी सामान्य वक्त नहीं देखा, क्योंकि, चीन की प्रवृत्ति धोखा देने, ठगने, झूठ घड़ने और आक्रामक होने की रही है। भारत और अपने अन्य संप्रभु पड़ोसियों के थलीय-जलीय इलाके में अपना विस्तार करने, बलात हथियाने या कब्जा करने की चीनी कोशिशें, उसकी मंशा का सुबूत हैं, जिसको पूरी दुनिया

जानती और मानती है।

चीन और भूटान के बीच सीधा संपर्क बनने से पैदा होने वाले खतरे को, सभ्य देशों की आचार संहिता के संबंध में एक कपोल-कल्पना न समझा जाए। इसके पीछे छिपी है असामान्य भू-राजनीतिक और कब्जाने एवं दबाने की भू-आर्थिकी चालदृ यह उस नीति का अंग है, जो जिनपिंग ने निरोल रूप से भारत के लिए अपना रखी है। भूटान-चीन के बीच सीधा संपर्क यानी भारत के वजूद के लिए खतरा और बहुत बड़ा भूभाग गंवाने की आशंका।

बताया जा रहा है, अपनी बीजिंग यात्रा में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरज़ी ने चीनी उप-राष्ट्रपति हान झेंग और विदेशमंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद चीन से सीमा विवाद पर 'बड़ी प्राप्ति' हासिल की है। उन्होंने चीन के साथ मिलकर काम करने की भूटान की इच्छा दर्शायी है। चीन ने भी भूटान में अपना दूतावास खोलने की पुरानी इच्छा दोहराई है। भारत को अवश्य ही इस कदम का पुरज़ोर विरोध करना चाहिए। भारत के वजूद के चलते चीन भूटान में अपनी उपस्थिति महसूस नहीं करवा सकता।

बतौर नीतिगत मामला, भूटान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों के साथ (चीन सहित) दूतावास स्तर के राजनयिक संबंध नहीं हैं। इसलिए भूटान द्वारा चीन को राजनयिक पहुंच प्रदान करने से अन्य चार देशों के लिए भी दरवाज़ा खुल जाएगा। संप्रभु भूटान को याद रखना होगा कि हिमालय के पर्यावरणीय रूप से नाज़ुक क्षेत्र में स्थित होने की वजह से वह विदेशियों की बाढ़ के लिए द्वार खोलना गवारा नहीं कर सकता। चीन के प्रवेश के बाद अन्य देशों की आमद होने पर 'स्वर्ग का पुत्र' (शी जिनपिंग) भूटान को नर्क बनाने पर तुल जाएगा। भूटान का भविष्य भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाए रखने में है, जिसकी मंशा न तो अपने पड़ोसियों को बंधुआ बनाने की है न ही उन्हें कर्ज के पहाड़ तले दबाने या जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने की या नस्लकुशी करने की। इसीलिए भारत की नीति सदा एक मिसाल रही है। क्या हमारे समुद्र तट विहीन दो पड़ोसी देश-भूटान और नेपालदृ के नागरिकों को भारत आने के लिए पासपोर्ट अथवा वीज़ा लेना पड़ता है? अपने एक अन्य पड़ोसी किंतु दुश्मन राष्ट्र के नागरिकों द्वारा समय-समय पर किए आपराधिक कृत्यों को झेलने के बावजूद भारत चीन के बरक्स भूटान का वैकल्पिक दोस्त नहीं बन सकता।

अभिजीत भट्टाचार्य

मौजूदा हालात में जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर भारत को आज जितना सतर्क रहने की जरूरत है, इससे पहले कभी नहीं थी। ड्रैगन इस वक्त बहुत तेज़ी में है क्योंकि शी जिनपिंग को और गवारा नहीं है कि भारत एक मातहत न बने जैसा कि उन्होंने अन्य छोटे और कमज़ोर मुल्कों और बीआरआई/सीपीईसी वाले देशों को पिछलग्गू बनाकर किया है। भूटान एशिया का एकमात्र राष्ट्र है जिसके चीन के साथ राजनयिक स्तर के संबंध नहीं हैं, यह बात चीनी राष्ट्रपति के लिए बेइज्जती महसूस करने का सबब बनी हुई है। इसलिए जैसे भी हो, भूटान को भी अपनी छत्रछाया में लेना है और भूटान को हड़पने का यह मंज़र भारत मन-मसोसकर देखेदृ चीन की सोच का यही लक्ष्य है।

चीन को अपने अड़ोस-पड़ोस में दबदबा कायम करने में किसी किस्म की बाधा अब चाहे छोटी या बड़ी स्वीकार नहीं है। इस उपमहाद्वीप से होकर गुज़रते थलीय एवं जलीय मार्ग सामरिक रूप से उसके लिए बहुत अहम और जरूरी हैं और चीन की प्रगति गाथा के समांतर उनको छोड़ नहीं जा सकता।

यहां ज़रा गलती न होदृ यदि भारत और भूटान अपना एका और आपस में गुथे उप-हिमालयी भूभाग रूपी सांझी गर्भनाल को तोड़ देंगे, तो इस स्वनिर्मित बर्बादी के लिए दोनों ही दोषी करार होंगे।

आमसभा में प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं की अनुपस्थिति बनी जन चर्चा का विषय

शराब और लव जिहाद को मुद्दा बना गए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लाडली बहना योजना का प्रचार कर रही भाजपा की सभा में महिलाएं रही नदारद

माही की गूंज, शाजापुर। अजय राज केवट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासकीय जेएनएस कॉलेज ग्राउंड पर चुनावी आमसभा को संबोधित किया। वे यहां भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। तय समय से करीब 20 मिनट देरी से सभा स्थल पर पहुंचे योगी का उद्बोधन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के विकास पर कम और हिंदुत्व पर ज्यादा रहा। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। जिस लाडली बहना योजना को भाजपा शिवराज सरकार की बड़ी उपलब्धि बता कर जोर-शोर से प्रचार कर रही है उस लाडली बहना योजना का योगी ने अपने उद्बोधन में एक बार भी जिक्र नहीं किया जो जन चर्चा का विषय रहा। आमसभा में महिलाओं की उपस्थित नहीं बराबर होने से भाजपा के नेता चिंतित नजर आए। आमसभा में कॉलेज के छात्र-छात्राओं को भाजपा का दुपट्टा डालकर दर्शक दीर्घा में जबरन बैठने की बात भी सामने आ रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की आम सभा को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा बड़ा जनसमुदा इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा था वही आमसभा में करीब 4 हजार लोगों की उपस्थिति ने भाजपा नेताओं के दावे झूठा साबित कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुजालपुर विधानसभा में शराब और पोलायकलां में लवजिहाद को मुद्दा बना गए। उन्होंने शुजालपुर में कहा कि, आपको तय करना है शिक्षा संस्कार चाहिए या फिर शराब और उससे बर्बादी। दूसरी ओर पोलायकलां में वह बोले कि, कांग्रेस प्रत्याशी को तो लवजिहाद से ही फुर्सत नहीं थी। उनका जिहादियों को ही प्रश्रय था। वह बोले की लवजिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। योगी ने जब मंच से शराब माफिया और लव जिहाद को लेकर बोले तो सभा में मौजूद जनसमुदाय ने उत्साहित होकर योगी का अभिवादन किया।

भाजपा के दिग्गज नेता रहे नदारद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आमसभा में योगी के साथ मध्य प्रदेश भाजपा के किसी भी दिग्गज नेता का नही आना कई सवाल खड़े कर गया। आम सभा के बाद यहा चर्चा जोरों पर रही कि, शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के सामने मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे कर दिया, जबकि भाजपा अपने चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का जमकर प्रचार-प्रसार कर रही है।

कार्यक्रम में भाजपा की अंतर कलह हुई उजागर

लगातार 10 वर्ष तक शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे जसवंत सिंह हाडा की चुनावी सभा में अनुपस्थिति भी नागरिकों की चर्चा का विषय रही। कांग्रेस ने जहां हाड़ा की अनुपस्थिति को भाजपा की अंतर कलह बताया है वहीं भाजपा इसे हाड़ा की चुनावी व्यवस्था बता रही है। गौर करने वाली बात है कि पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा को शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक सर्वाधिक विकास कार्य करने वाला विधायक माना जाता है। बता दें कि जसवंत सिंह हाड़ा शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट के प्रबलतम दावेदार थे। सूत्रों की माने तो भाजपा द्वारा कराए गए कई सर्वे में भी हाडा जनता की पहली पसंद थे।

योगी ने सिकरवार को बताया शराब व्यापारी, कांग्रेस ने पूछा सुदेश राय कौन है...?

योगी ने अपने उद्बोधन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार को शराब व्यापारी बताकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने पड़ोसी जिले की सीहोर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान विधायक सुदेश राय पर सवाल खड़ा करते हुए कहां की सुदेश राय भी तो शराब व्यापारी हैं, भाजपा ने उन्हें क्यों टिकट दिया...?

कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्ष से भाजपा की सरकार है, अगर शराब व्यापार से इतनी ही नफरत है तो सरकार ने प्रदेश में शराब बंदी क्यों नहीं लागू की। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती कई वर्षों से मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मांग कर रही हैं।

कांग्रेस ने कहा, पोचानेर में किसने बैंककर्मी के साथ मारपीट की...?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए आमसभा में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज खत्म किया है। योगी के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि, शायद योगी को शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बारे में जानकारी नहीं है, यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार के परिजनों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। वीडियो इंदर सिंह परमार के गृह ग्राम पोचानेर का है वही उसके साथ मारपीट भी हुई बैंक कर्मचारी का दोष सिर्फ इतना था कि उसने पासबुक बनाने के लिए लगने वाले शुल्क 150 जमा करने की बात इंदर सिंह परमार के भाई से कही थी जो उनके परिजनों को नागवारा गुजरी।

शराब पीने के आरोप में चूहा गिरफ्तार, अदालत में पेश करेगी पुलिस

छिंदवाड़ा।

मध्य प्रदेश में पुलिस ने शराब की बोतलें खाली करने के आरोप में एक चूहे को 'गिरफ्तार' किया है। हैरान कर देने वाली यह घटना प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सामने आई है। जहां एक पुलिस स्टेशन में जब्त करके रखी गई शराब की 60 बोतलों को चूहों ने खाली कर दिया।

पुलिस का कहना है कि, उसने प्लास्टिक की बोतलों में पैक अवैध शराब को जब्त करने के बाद पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में रख दिया था, लेकिन चूहों ने उनमें से 60 बोतलों को खाली कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक चूहे को 'गिरफ्तार' किया है और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

चूहों पर लगाए कई 'गंभीर' आरोप

पुलिस का कहना है कि, थाने की इमारत बहुत पुरानी है, जहां चूहे अक्सर घूमते देखे जाते हैं। उसका कहना है कि कई बार ये चूहे कुतरकर रिकॉर्ड भी नष्ट कर देते हैं। पुलिस ने 'आरोपी' चूहों में से एक को 'गिरफ्तार' करने का दावा करते हुए कहा कि उसे सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि शराब पार्टी में कितने चूहे शामिल थे। जिस मामले में शराब की बोतलें जब्त की गईं, वह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

पहले भी सामने आ चुके है ऐसे मामले

पुलिस को अब अदालत में जब्त की गई शराब पेश करनी है, ऐसे में उसे अपना पक्ष रखने में मशक्कत करनी पड़ रही है। यह पहली बार नहीं है जब चूहों पर पुलिस स्टेशन में शराब पीने का आरोप लगा है। इससे पहले पुलिस ने शाजापुर जिला अदालत में एक ऐसी ही घटना सुनाई थी तो जज और कोर्ट का पूरा स्टाफ हंस पड़ा था। यूपी में भी 2018 में बरेली के छावनी पुलिस स्टेशन के गोदाम में रखी एक हजार लीटर से ज्यादा जब्त शराब गायब हो गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने शराब गटकने का आरोप चूहों पर लगाया था।

सोने-चांदी और नोटों से सजने लगा महालक्ष्मी का दरबार

सोना-चांदी, आभूषण, मोती, हीरे और नकदी से सजावट शुरू हो गई है। विशेष शृंगार भाई दूज तक रहेगा। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में सात नवंबर की रात 11 बजे तक सामग्री दी गई।

माही की गूंज, रतलाम।

10 नवंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय दीपोत्सव में रतलाम के माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए इस बार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण 50 हजार रुपए से ज्यादा की नगदी नहीं ली जा रही है।

हर बार की तरह इस बार भी शृंगार के लिए सामग्री देने वाले श्रद्धालुओं को टोकन दिया गया। इसी टोकन के आधार पर सामग्री वापस भी की जाएगी। मंदिर के संजय पुजारी ने बताया कि, आठ व नौ नवंबर को दिन भर शृंगार व सजावट का काम चलेगा। दीपोत्सव में शृंगार रहने तक मंदिर में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अभी तक 351 भक्त सामग्री दे चुके हैं।

कुबेर पोटली बनाने का काम शुरू

रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर बार धनतेरस पर कुबेर पोटली बांटी जाती है, लेकिन कोरोना काल में इस पर रोक लगा दी गई थी। इस बार कुबेर पोटली बांटी जाएगी, लेकिन समय तय नहीं हुआ है। सामग्री रखने वाले श्रद्धालुओं को भी पोटली मिलेगी। कुबेर पोटली में सीपी, सुपारी, कमल गट्टा, सिक्का आदि सामग्री रहती है। मान्यता है कि इसे घर की तिजोरी में रखने से समृद्धि बनी रहती है।

नोटों, जेवरों से होती है विशेष सजावट

उल्लेखनीय है कि, प्रति वर्ष श्रद्धालुओं द्वारा दी गई सामग्री से महालक्ष्मी मंदिर की सजावट के बाद पट धनतेरस पर तड़के शुभ मुहूर्त में खोले जाते हैं। पांच दिवसीय दीपोत्सव में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले आभूषण, हीरे, मोती, तिजोरी, नकदी आदि से की गई सजावट भाई दूज तक रहती है। इसके बाद श्रद्धालुओं को उनकी सामग्री वापस कर दी जाती है। मान्यता है कि मंदिर में सामग्री देने के बाद वापस लेकर घर में रखने पर वर्षभर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

बड़े बालाजी मंदिर में देव दिवाली पर लगेगा 56 भोग का नैवेद्य

माही की गूंज, मंदसौर।

बड़े बालाजी मंदिर समिति द्वारा देव दिवाली पर 11 नवम्बर को आयोजित होने वाले हनुमान प्रकटोत्सव दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 11 नवम्बर को बालाजी भगवान की महाआरती के साथ ही 56 भोग का नैवेद्य भी लगाया जाएगा। 56 भोग के निर्माण हेतु 7 नवम्बर को विधि विधान से भट्टी पूजन किया गया। भट्टी पूजन पं. सत्यनारायण जोशी द्वारा सम्पन्न कराया गया। साथ ही मंदिर क्षेत्र को भगवा पताकाओं व झीलमिलाती विद्युत सज्जा से भी सजाया जा रहा है।

मंदिर समिति के अध्यक्ष पं. दिलीप शर्मा व प्रवक्ता रवि ग्वाला ने बताया कि, दिनांक 11 नवम्बर देव दिवाली पर दोप. 1 बजे 151 थालों में 56 पकवान सजाकर बालाजी को भोग लगाया जाएगा। तत्पश्चात् सायं 7 बजे 201 दीपक से महाआरती की जाएगी। जिसमें न्यू किशोर बैंड के 101 साथी मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। महाआरती की शोभा अजयमेरू के ढोल, उज्जैन की तोप व ताशे, अहमदाबाद की शहनाई व मंदसौर के 151 ढोल बढ़ायेंगे एवं इस दौरान भव्य रंगारंग आतिशबाजी भी की जाएगी।

नेता प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से बंदी लेते हैं इसलिए सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं- शेरपुर

पटवारी भर्ती निकाली उसमें भी पंद्रह-पंद्रह लाख रुपए लेके घोटाला कर दिया

माही की गूंज, रतलाम/जावरा।

निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर लगातार विधानसभा में दौरा कर मतदाताओं को आकर्षित करने में लगे हैं। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के भ्रमण के दौरान शेरपुर ने कहा कि, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में क्षेत्र के विकास और प्रकृति व क्षेत्र को शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर बनाने के लिए अपना अमूल्य वोट ऑटो रिक्शा पर देकर विजयी बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मान और सम्मान में कोई कसर नहीं छोडूंगा।

शेरपुर जनसंपर्क के दौरान सभा को संबोधित करते हुए बोले, किसानो की जरूरतमंद सामानो से जीएसटी हटें उसके लिए लडूंगा। आपके जो मुद्दे उठाएं वो पुरा करने के लिए सदन में लड़ना पड़े चाहे सड़क पर मैं लडूंगा। आपने 75 वर्षो से दोनों पार्टियों को वोट दिए हैं। मैं आपसे 5 वर्ष मांग रहा हूं। आपको लग जाएगा कि, आपने 75 वर्ष में जीनको वोट करा वो गलता किया या 5 वर्ष के लिए मुझे दिया वो गलत दिया। एक बार चेक करने के लिए वोट दे दीजिए आपको पता लग जाएगा आपकी हक और अधिकारी की लड़ाई कौन लड़ता है। किसानों को जिताना है तो ऑटो रिक्शा को जिताना होगा। पहले के क्रांतिकारीयो ने अंग्रेजों को भगाया था और देश आजाद करवाया था अब हमें इन पार्टियों को भगाकर देश को आजाद करांगे। नेता आते हैं और 8 लाइन बताते हैं कि हमने 8 लाइन बनाया है। क्या इस 8 लाइन से कोन ग़रीब किसान दिल्ली से मुंबई जाएगा।

सरकारी हॉस्पिटल ओर मेडिकल कॉलेज गुजरात मे भी यहां भी लगातार क्षेत्र के मुद्दों पर अपनी बात रख रहे है। जीवनसिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओ को घेरते हुवे कहा कि हम इलाज करवाने गुजरात जाते हैं। गुजरात में भी सरकारी हॉस्पिटल है हमारे रतलाम में भी सरकारी हॉस्पिटल है। गुजरात में भी मेडिकल कॉलेज है और हमारे रतलाम में भी मेडिकल कॉलेज है। लेकिन हमारे यहां न तो सरकारी अस्पताल की सही व्यवस्था है न मेडिकल कॉलेज की। गुजरात में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है लेकिन हमारे विधायकों में इतना दम नहीं है कि वह मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों की व्यवस्था सुधार दें। यह प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल वालों से नेता लोग बंदिया ले रहे हैं इसलिए यहां की व्यवस्था यह नहीं सुधार रहे हैं अगर यह व्यवस्था सुधार दें तो इनको बंदिया कौन देगा।

वैकेंसी नही, पटवारी भर्ती में कर डाला घोटाला

मध्यप्रदेश सरकार के पास बेरोजगारो के लिए कोई योजना नही है और पटवारी भर्ती निकाली उसमें भी घोटाला कर दिया। जो मेहनत से पढ़ने वाला वह फेल हो गया और जिसने 15 लाख दे दिए वह पटवारी बन गया। आम आदमी मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा सकता है 15 लाख नहीं दे सकता। इसके लिए भी विधायक को आवाज उठानी थी की जो घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए उसमें जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए लेकिन कुछ नहीं बोले व्यापम घोटाला हुआ? कितना बड़ा घोटाला था। पूरे देश ने देखा कितने गवाह थे सब मर गए। भाजपा-कांग्रेस एक है और दोनों चोर हैं।

कल जिले के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा में भरेंगे हुंकार

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का दौरा जारी है। इसी कड़ी में 10 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। जहां विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। जिसे लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं, पूर्व गृहमंत्री ने सीएम शिवराज के गांधी परिवार पर दिए गए बयान का पलटवार किया है।

पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने बताया कि, 10 तारीख को राहुल गांधी की राजपुर विधानसभा में आम सभा होने जा रही है। जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। खरगोन, अलीराजपुर, धार, झाबुआ जिले के भी लोग पहुंचेंगे। मीडिया से बातचीत में सीएम शिवराज के गांधी परिवार पर दिए बयान पर सवाल पूछने पर उन्होंने पटलवार करते हुए कहा कि, अगर इतनी मजबूत होते शिवराज सिंह तो उनकी पार्टी ने फिर से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया।

पूर्व गृहमंत्री ने आगे कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है। खुद की पार्टी शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास नहीं कर रही है। इतनी बुरी तरह असफल हो गए शिवराज सिंह और हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो सब की आंखें खुल जाएगी। उन्होंने 150 से अधिक सीट जीतने का दावा भी किया।

कंपनी में लूट के फरार मास्टर माईंड सहित तीन अरोपित गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

शहर के बिस्टान रोड स्थित सोनम जीनिंग में पांच माह पहले हुई लूट के फरार मास्टर माइंड सहित तीन आरोपितों को पुलिस ने पिछले दिनों गुजरात से पकड़ा है। उनके साथी पहले ही गिफ्तार हो चुके हैं। पुलिस द्वारा रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। 30 जुलाई की रात में चड्डी-बनियान गैंग ने लूट को अंजाम दिया था। बदमाशों ने लट्ठ और पत्थरों से जिनिंग कर्मचारियों पर हमला किया था। इसके बाद कार्यालय की अलमारी से करीब 8 लाख रुपए की नगदी लूटकर ले गए थे। लगभग दो महीने की जांच में खरगोन पुलिस को इस गैंग को पकड़ने में सफलता मिली थी।

इसमें पुलिस ने गुजरात के दाहोद में दबिश देकर विलेश पलाश, नरेश भाभोर और ड्राइवर विजय बिलवाल को गिरफ्तार किया था। गैंग का मास्टर माइंड विजय पुत्र दीपा भाई पलास 25 वर्षीय खजूरिया फाल्या जसवाड़ा दाहोद, सुनील उर्फ सुन्नैया पुत्र जौरसिंह बारिया 25 वर्षीय बड़वा जैसवाड़ा दाहोद व मनोज उर्फ मुन्ना बारिया 23 वर्षीय बिलवाल फालिया बड़वा जैसवाड़ा दाहोद को पकड़ा है।

आरोपित पहले रैकी करते थे। इसके बाद वाहन से आकर वारदाता को अंजाम देते थे। उज्जैन में भी पिछले साल इसी तरह चड्डी-बनियान गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। वे सभी आरोपी गुजरात के दाहोद जिले के निवासी थे।पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और 200 से अधिक बदमाशों से पूछताछ की थी। गैंग ने देवास, अंजड़, सिंघाना, सेंधवा, खेतिया, चापड़ा और बांसवाड़ा में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे चुकी है।

अन्य जीनिंग संचालकों में दहशत

वारदात के बाद शहर में संचालित 10 से ज्यादा जीनिंग मालिक दहशत में आ गए थे। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया है। अब पुलिस आरोपितों से पूछताछ करेगी। इसके अलावा अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।

5 लोगों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्रवाई

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 5 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है और 4 लोगों के विरूद्ध थाना प्रभारी के समक्ष बंधपत्र भरवाने का आदेश दिया गया है।

जिला बदर किए गए 5 लोगों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में जुआ खेलने, अवैध शराब बेचने, हथियार रखने, लोगों के साथ मारपीट करने व गालियां देने संबंधी कई प्रकरण दर्ज है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इन 5 लोगों में तवड़ीपुरा सनावद निवासी नारायण ऊर्फ डॉन पिता बाबुलाल बेसवार, तवड़ीपुरा सनावद निवासी करण पिता निर्मल ऊर्फ निम्मु, ढापला हामु महालक्ष्मी नगर महेश्वर निवासी रोशन पिता दरियाव वर्मा, चन्दर कॉलोनी बेड़िया सनावद निवासी आकाश पिता बाबुलाल सोलंकी, अडा बाजा इंदौर, हा.मु. एमजी रोड़ शीतला माता मंदिर महेश्वर निवासी श्याम पिता सत्यनारायण जोशी शामिल है। ग्राम उबदी निवासी जितेन्द्र पिता शेरू भालसे को 50 हजार रुपए, चमेली की बाड़ी खरगोन निवासी अंतिम पिता बाबुलाल सेन को 25 हजार रुपए, राजपुत मोहल्ला महेश्वर निवासी शैलेन्द्र पिता नयनसिंह सोनेर को 25 हजार रुपये, मण्डी रोड़ भीकनगांव निवासी आनंदा पिता बालुजी मेहता को 25 हजार रुपए का बंधपत्र थाना प्रभारी के समक्ष भरकर 06 माह तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को थाना प्रभारी के समक्ष अपनी आमद देने कहा गया है। इन 5 व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 379, 376, 366, 452, 323, 506, 34, 294, 341, 324, 147, 436, 427 एवं 34 (ए) आबकारी एक्ट, 13 जुआ एक्ट, 25 बी आर्म्स एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।

नुक्कड़ नाटक से दिया बिना डरे और बिना ललचाए मतदान करने का संदेश

माही की गूंज, बड़वानी।

शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित की जा रही स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत प्राचार्य डॉ. दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके बिना डरे और बिना ललचाये मतदान करने का संदेश दिया गया।

यह थी नाटक की थीम

कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया और वर्षा मुजाल्दे ने बताया कि इस नाटक की मुख्य थीम शत-प्रतिशत मतदान को सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरूकता उत्पन्न करना था। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया।

ये दिया गया संदेश

नाटक के लेखक राहुल वर्मा एवं सुरेश कनेश ने बताया कि नाटक की शुरुआत में उन मनमौजी युवाओं को जाग्रत किया गया, जो मोबाइल की दुनिया में खोये हुए हैं। उन्हें रील्स से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाया गया। अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन और चालीस प्रतिशत से अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगों के लिए घर-घर जाकर वोट डलवाने की व्यवस्था समझाई गई। महिलाओं को मतदान के लिए घर से निकलने के लिए प्रेरणा दी गई। शराब, पैसा या किसी अन्य वस्तु की लालच में अपने वोट को नहीं बेचने या किसी से डरकर अपने वोट का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग नही कर पाने तथा विवेकपूर्वक मताधिकार के उपयोग का संदेश दिया गया।

इन्होंने निभाई भूमिकाए

नाटक में सुरेश कनेश, सुनील मेहरा, अक्षय चौहान, वर्षा मुजाल्दे, स्वाति यादव, सतीश अवास्या, सुभाष चौहान, पूनम कुशवाह, हिम्मत कनेश आदि ने विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया। सहयोग कन्हैया फूलमाली, डॉ. मधुसूदन चौबे ने किया।

वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बराती

माही की गूंज, बड़वानी।

भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय पाटी में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्रा तरूणा वर्मा ने ''जैसे फूल- फूल चुनकर ही चमन बनता है, वैसे वोट- वोट जुड़कर ही प्रजातंत्र का भवन बनता है'' कु रूपाली वर्मा ने लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें कविता से मतदान का संदेश दिया। प्रथम वर्ष की छात्रा जागृति कुमावत ने चुनाव नहीं मतदान करें, नवभारत का निर्माण करें एवं सपना धनगर ने देश के मतदाता है वोट देना आता है, द्वितीय वर्ष की छात्रा निर्मला सस्ते ने हे मतदाता हे राष्ट्र निर्माता कविता से बिना किसी लालच के मतदान करने का अनुरोध किया। छात्र बिल्लौरसिंह सोलंकी और सियाराम जमरे ने वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बानो बराती कविता से युवाओं को संदेश देकर मतदान की अनिवार्यता और वोट की शक्ति का महत्व बताया।

मतदान पर काव्य पाठ प्रतियोगिता में कु तरूणा वर्मा ने प्रथम, कु रूपाली वर्मा ने द्वितीय एवं जागृति कुमावत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय द्वारा तीनों विजेताओं को गिफ्ट दिए गए तथा समस्त प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप कलम भेंट की गई। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ परवेज मोहम्मद ने विद्यार्थियों से महाविद्यालय के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का राजदूत बनने का आग्रह किया और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक वोट डालने के लिए संदेश भेजने हेतु प्रेरित किया। प्रतियोगिता में डॉ. नारायण पाटीदार एवं प्रो. राजू ओसारी ने निर्णायक की भूमिका निभाई तथा कार्यक्रम का संचालन स्वीप गतिविधि नोडल प्रभारी प्रो. अंजू बाला जाधव ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के भारत सिंह चौहान, जगदीश जमरे, शिवजी सोलंकी, सखाराम, कनसिंह, विक्रम तथा कई विद्यार्थी उपस्थित थे।

सामग्री वितरण की व्यवस्था का जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा

माही की गूंज, बड़वानी।

विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने बुधवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर बड़वानी में बनाये गये सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 16 नवंबर को विधानसभा बड़वानी के मतदान दलों को प्रातः 7 बजे से सामग्री का वितरण होना है, अतः सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अभी से पूर्ण कर ली जाये। मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री का बस्ता बनाकर उन्हे वितरित किया जाये साथ ही उन्हे यह भी निर्देशित किया जाये कि वे अपने दल के सदस्यों के साथ दी गई सामग्री का मिलान करने के पश्चात् ही मतदान केन्द्र के लिए रवाना हो। मतदान दलों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। इस दौरान कलेक्टर ने सामग्री वितरण स्थल, विधानसभा बड़वानी के स्ट्रांग रूम, पार्किंग स्थल, प्रवेश द्वारा का भी निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, अपर कलेक्टर केके मालवीय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोहन कनाश, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती विशाखा देशमुख एवं विवेक गुप्ता सहित सामग्री वितरण प्रबंधन के नोडल अधिकारी आरएल जामरे, प्रजापति उपस्थित थे।

जिले के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र पाटी के मतदाताओं ने किया घर पर अपने मताधिकार का उपयोग

माही की गूंज, बड़वानी। विधानसभा बड़वानी के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र विकासखण्ड पाटी के ग्रामों में 10 ग्रामीणों के द्वारा घर पर अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इस दौरान वृद्धजन एवं दिव्यांग जनों के परिजनों ने बताया कि दुर्गम क्षेत्र होने से उन्हे मतदान करने जाने में असुविधा होती है, परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो सुगम मतदान की सुविधा दी गई है, उसके कारण वे मतदान कर पाये है। जानकारी अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के ग्राम बमनाली निवासी रेलबाई लुदा एवं बुटी सिकला ने, ग्राम घुघसी निवासी सुतारिया थावरिया, काहरी ओनू तथा खुशाल मोना ने, ग्राम मुवासवाड़ा निवासी सुरमी सुरभान ने तथा नलती निवासी दलीबाई कोल्या, बुदलीबाई खुमसिंह, कालू देवजी तथा डेटली बेलदार ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ घर पर मतदान बड़वानी शहर की पानवाड़ी निवासी जेहरा बी ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक रूबल अग्रवाल भी उपस्थित रही। प्रेक्षक ने उन्हे आयोग की सुगम मतदान सुविधा के बारे में बताते हुए मतदान की जानकारी दी।

आबकारी विभाग की टीम ने 4.33 लाख रुपए की कच्ची मदिरा एवं महुआ लहान की जब्त

माही की गूंज, खरगोन।

विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने 4 लाख 33 हजार 500 रुपये का महुआ लाहन एवं कच्ची मदिरा जब्त की है।

आबकारी वृत अ, ब, स, तथा कसरावद के संयुक्त दल द्वारा आज दिनांक 7 नवंबर 2023 को सहायक जिला आबकारी अधिकारी टीआर गंधारे के नेतृत्व में अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरुद्ध खरगोन स, के ग्राम खडकिया घाट, वासखेडी व लालपुरा में दबिश दी गई। इस दौरान वृत्त प्रभारी दिनेश चौहान द्वारा म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा 4000 किलोग्राम महुआ लाहन व निर्माण सामग्री बरामद की गई है। जब्त मदिरा, महुआ लाहन व निर्माण सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख 33 हजार 500 रुपये है। इस कार्यवाहीं में आबकारी उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह भदोरिया, ओम प्रकाश मालवीय, आबकारी आरक्षक रणजीत वर्मा, संता चौहान, अमन चौहान, जगदीश पाटीदार, राजू डुडवे, नवनीत पाल, संतोष वर्मा शिवनारायण कटारे, रीता सिंगोरिया का सराहनीय योगदान रहा है।

दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से डाकमत से मतदान कराने घर-घर जायेंगे मतदान दल

माही की गूंज, खरगोन।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र मतदान करने नहीं आ सकते हैं, उन्हें डाकमत पत्र के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के मुताबिक खरगोन जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे 810 मतदाताओं से मतदान कराने 8 नवंबर से मतदान दल उनके घर पहुंचेंगे। डाकमत पत्र से घर से मतदान करने की फार्म 12-डी में सहमति देने वाले इन मतदाताओं से मतदान कराने चलित मतदान दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक पीठासीन अधिकारी और एक मतदान अधिकारी क्रमांक एक होगा। इनके अलावा एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुरक्षा कर्मी, एक वीडियोग्राफर भी दल के साथ मौजूद रहेगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से डाकमत पत्र से मतदान की दी गई सुविधा के तहत मतदान दल पहले चरण में 8 और 9 नवंबर को इन मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और मतदान करायेंगे। इस दौरान यदि वे अनुपस्थित रहे तो दूसरे चरण में मतदान दल दोबारा उनके घर पहुंचेंगे। इसकी बकायदा घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को सूचना दी जायेगी जिसमें दिन और समय का उल्लेख भी रहेगा। दोबारा भी घर में अनुपस्थित रहने पर ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा नहीं होगी वे मतदान केन्द्र पर जाकर भी अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से घर-घर जाकर डाकमत पत्र से मतदान कराये जाने वाले मतदान दलों के रूट चार्ट की सूचना चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को दी जा चुकी है। मतदान के दौरान उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ता अथवा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ता भी दिव्यांग एवं अस्सी प्लस मतदाताओं के घर पर मौजूद रह सकेंगे। मतदान की इस समूची प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी भी कराई जायेगी।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव से 186, बड़वाह से 139, महेश्वर से 102, कसरावद से 88, खरगोन से 186 एवं भगवानपुरा से 109 दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदान केन्द्र में आने में असमर्थ मतदाताओं ने घर से मतदान कराने फार्म 12-डी में आवेदन प्रस्तुत किया है। यह मतदाता अपने घर से डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगें।

बेबाकी के साथ...सच
माही की गूंज
एजेंसी देना है
झाबुआ जिले में
रंभापुर, मदरानी, झकनावदा, खवासा, राणापुर
अलीराजपुर जिले में
सौंडवा, कट्ठीवाड़ा, छकतला, चांदपुर, बोरी
संपर्क - 9589882798, 9981318651

सोने के सिक्के के मामले में नार्को टेस्ट से मुकरे आरोपी पुलिस वाले

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले के चर्चित सोना सिक्का कांड में अब नया मोड़ आते दिखाई दे रहा है। मामले के आरोपी सोंडवा थाने के तत्कालीन टीआई सहित तीन अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों ने अहमदाबाद की एक लेबोरेटरी में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट ओर पोलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए मना कर दिया है। पुलिस आरोपियों को लेकर बीते 16 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंची थी। इसी बीच इंदौर हाईकोर्ट ने आरोपी टीआई सहित तीन पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय दिया है कि, अलीराजपुर पुलिस नार्को सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए आरोपी पुलिसकर्मियों की सहमति लेने का प्रयास करें और सहमति होने पर ही आगे के टेस्ट करवाएं।

एसपी अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि, पहले टीआई को छोड़कर तीन पुलिसकर्मियों ने नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी थी लेकिन बाद में मुकर गए। अब हम फिर से सहमति लेने का प्रयास कर रहे हैं।

पीड़िता ने की सीबीआई जांच की मांग

इस सोना सिक्का चोरी कांड में अब पीड़िता रमकुबाई ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सहित मध्यप्रदेश के गृमंत्री को एक शिकायत पत्र भेजकर पुरे मामले की जांच सीबीआई या सीआईडी से करवाने की मांग की है। अपने शिकायती पत्र में रमकुबाई ने लिखा कि, मामले में पहले दिन से ही पुलिस आरोपियों को सहयोग कर रही है।

पुलिस रिमांड में भी लूटे गए सोने के सिक्के नहीं बरामद कर सकी। इसके अलावा जिला जेल में पहचान परेड के दौरान में पुलिस, राजस्व और जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस कोशिश मे? लगे रहे कि वह पहचान में विफल हो जाएं ताकि आरोपियों को? फायदा हो सके।

सारे दांव-पेच जानते हैं आरोपी पुलिसवाले- पीड़िता

अपनी शिकायत में पीड़िता रमकुबाई ने लिखा है कि, आरोपी पुलिसकर्मी हैं और वो सारे दांव-पेच जानते हैं कि कैसे अपराध कर बचा जा सकता है। साथ ही स्थानीय पुलिस उनसे मिली हुई है, इसलिए उन्हें अब भरोसा नहीं है कि न्याय मिल सकेगा। इसलिए मामले की जांच अलीराजपुर जिले की पुलिस से न करवाकर अब या तो सीबीआई को दी जाए या सीआईडी जैसी एजेंसी उनके मामले की जांच करे। तभी सिक्के वापस मिलने और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद होगी।

ये है पूरा मामला

अलीराजपुर जिले के सोंडवा सोना सिक्का चोरी कांड मध्यप्रदेश के साथ ही देश बहुचर्चित अपराधों में से एक है। इसमें आरोप है कि सोंडवा थाने के तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा ने अपने तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जाकर बैजड़ा गांव की रमकुबाई और उसके जेठ के घर से 240 ब्रिटिशकालीन यूनीक सिक्के धमकाकर ले लिया। पुलिस रोजनामचे में शराब पकड़ने के लिए बैजड़ा गांव जाना बताया गया था। घटना 19 जुलाई 2023 की है। मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सोडंवा थाने पर ही धारा 379, 392, 452, 294, 166 I, 420 और 409 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के 36 दिन बाद आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी तो हुई लेकिन एक पखवाड़े के रिमांड के बावजूद पुलिस उनसे पूछताछ में न अपराध कबूल करवा सकी और न सिक्कों की बरामदगी करवा सकी।

पीड़िता रमकुबाई और उसके परिवार को? सोने के सिक्के गुजरात में मजदूरी के दौरान एक पुराने घर को तोड़ने के दौरान मिले थे। भारतीय बाजार में चोरी गए सिक्कों की कीमत करीब 1 करोड़ तो यूनिक हैरीटेज इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी।

विधानसभा चुनाव में बारात जैसा माहौल

सैकड़ो महिलाओं ने सेना पटेल का नाम लेकर गाऐ गीत

माही की गूंज, आम्बुआ।

वर्तमान समय विधानसभा 2023 के चुनाव का चल रहा है। जिधर देखो उधर चुनावी रंगत बिखरती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशी अधिक ध्यान दे रहे हैं कारण की ग्रामीणों की एक आदत रहती है कि वह सामूहिक निर्णय लेते हैं तथा हवा का रुख देखते हैं कि किस पार्टी की हवा चल रही है। हालांकि वह इतने चतुर भी है कि प्रचार करने आने वाले कौन है कहां के हैं आदि का ध्यान रखकर ही बात करते हैं। मगर जुबान के पक्के जिसे वचन दे दिया वह निभाते जरूर है। कुछ अपवाद हो सकते हैं जब कुछ मतदाता शराब और पैसों के लालच में दल बदल ले मगर कम ही ऐसा होता है। यह प्रतिनिधि कई ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर चुका मगर ऐसा नजारा एक ही जगह देखने को मिला जब प्रत्याशी के पक्ष में होने वाली बैठक में सैकड़ो महिलाओं ने विवाह में आने वाली बारात की तरह व्यवस्था कर प्रत्याशी के पक्ष में लोकगीत गाकर समां बांध दिया।

गूंज संवाददाता इन दिनों चुनावी चहल-पहल देखने हेतु प्रत्याशियों के साथ अथवा अपनी स्वयं की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर विधानसभा चुनावी हलचल देख सुन रहे हैं। 6 नवंबर को एक ग्रामीण क्षेत्र में शाम को चुनावी चौपाल सजी मिली, जिसमें ग्रामीण पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की दिखी, जैसे विवाह समारोह में सिर पर टोकरी लेकर दुल्हन की बहन चलती है, वैसे ही यहां ग्रामीण महिलाएं बैठक में उपस्थित हुई। सैकड़ो की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर में लोकगीत गाना प्रारंभ किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सेना महेश पटेल (विधानसभा क्षेत्र 192 की प्रत्याशी) के पक्ष में नाम ले-लेकर गीत गाए गए। पुछने पर बताया कि, वह पिछले वर्षों से गांव परिवार वालों के साथ अन्य पार्टियों को वोट डालते रही है मगर इस बार वे सेना पटेल को वोट देंगे तथा जिताऐगी। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि बदलने की हवा चल रही है बहुत समय हो गया है अब बदलना चाहिए।

ग्रामीणों की यह सोच कैसे और क्यों आ रही है यह पूर्व में जीते प्रत्याशी ही अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ग्रामीण उन्हें क्यों नकार रहे हैं। वैसे इनका यह रुझान कितना असर दिखाएगा, यह 17 नवंबर तथा 3 दिसंबर को परिणाम के बाद पता चलेगा।

रेस्टोरेंट संचालक पर हमले का आरोपित हिस्ट्रीशीटर जग्गू गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

औद्योगिक थाना क्षेत्र के डोंगरे नगर में रेस्टोरेंट संचालक पर जानलेवा हमला करने व उसके भाई, भानेज के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित हिस्ट्रीशीटर 22 वर्षीय विकास उर्फ जग्गू पुत्र हेमराज मेघवाल निवासी हिम्मतनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए भागने के दौरान व गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। उसके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।

ये था मामला

रतलाम पुलिस के अनुसार 5 नवंबर की रात प्रफुल्ल पंवार निवासी डोंगरे नगर क्षेत्र स्थित अपने रेस्टोरेंट पर बैठे थे। आरोपित विकास उर्फ जग्गू व उसके दो अन्य साथी सिगरेट लेने रेस्टोरेंट पर गए थे। आरोपितों ने सिगरेट ली तो दुकानदार ने रुपये मांगे। इस पर एक आरोपित कहने लगा कि, रुपये दे दिए हैं। प्रफुल्ल ने रुपये नहीं देने की बात कहते हुए दोबारा रुपये मांगे तो आरोपित गाली-गलौच करने लगे। इसी बीच शोर सुनकर प्रफुल्ल का छोटा भाई संजय व भांजा अनमोल रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो आरोपित वहां से चले गए थे ।कुछ देर बाद विकास व अन्य साथियों ने बाइकों से रेस्टोरेंट पर पहुंचकर रेस्टोरेंट संचालक प्रफुल्ल पर लोहे की चेन, बेल्ट, ईंट, पत्थर से हमला कर दिया था।

स्वजनों ने भी की मारपीट

घायल होकर प्रफुल्ल नीचे गिर गया तो भी आरोपित उसे मारते रहे थे। भाई संजय व भांजा अनमोल बीच-बचाव करने गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी। पुलिस ने विकास व उसके साथियों के खिलाफ भादंवि की धारा 294, 307, 147, 148, 149, 506 के तहत बलवा व जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया गया है।

रेस्टोरेंट संचालक, उसके भाई व भांजे के साथ की गई मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। इधर औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी। इसी बीच पुलिस के अनुसार सोमवार रात सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपित विकास उर्फ जग्गू मोहनगर क्षेत्र में कामर्स कालेज के पास है।

पुलिस देखकर भागा

पुलिस टीम पकड़ने पहुंची तो वह भागने लगा और गिर गया, जिससे उसके हाथ, पैर में चोट आई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि, सीसीटीवी फुटैज से उसके साथियों में सौरभ वर्मा, दर्पण राठौड़, हर्ष सोनी व एक अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपित जग्गू को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उस पर मारपीट, धमकाने सहित अन्य मामलों के पांच जबकि सौरभ वर्मा पर 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों रैली आयोजित

जिला स्वीप आईकॉन सुधीर जैन ने की सहभागिता

माही की गूंज, आम्बुआ।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशन एवं जिला स्वीप नोडल अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आम्बुआ के विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा ग्राम में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिला स्वीप आईकॉन समाजसेवी व एडवोकेट सुधीर जैन ने सहभागिता की। विद्यालय प्रांगण से निकाल कर यह रैली बस स्टैंड होकर ग्राम के मुख्य बाजार से होती हुई पुनः विद्यालय में समाप्त हुई। रास्ते भर पीसीओ मनोहर वाणी व विद्यार्थी मतदान करने के लिए नागरिकों को जागरुक करते रहे विशेष कर बाजार का दिन होने से स्थानीय ग्रामीण जनों को क्षेत्रीय आदिवासी भाषा में भी समझाइश दी गई और 17 नवंबर को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। मतदाता जागरूकता के बैनर एवं तख्तियां लेकर लेकर विद्यार्थी इस रैली में चल रहे थे। इस रैली के समापन पर विद्यालय प्रांगण में जिला स्वीप आईकॉन सुधीर जैन ने विद्यार्थियों और मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय के शिक्षकों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र भारद्वाज, अध्यापक गोयल, स्टाफ, आईसीडीएस सुपरवाइजर उषा भाबर, पंचायत सचिव नवल सिंह डुडवे एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

मतदान कर्मियों को दिया सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण

माही की गूंज, मंदसौर।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संपादन के लिए नियुक्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिये नियुक्त किया गया है।उन मतदान दल कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 16 कक्षों में एवं कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में जिले के मास्टर ट्रेनर्स एवं अन्य सहायक मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान कर्मियों को सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कहा गया कि, मतदान में पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान दलकर्मी सैद्धांतिक के साथ ही गहनता से प्रशिक्षण लें, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी न आए। पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका का भलीभांति अध्ययन कर लें। प्रशिक्षण में मतदान दल कर्मियों को ईवीएम, व्ही.व्ही.पैट मशीन, वेलिट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट की कार्यप्रणाली एवं इनमें उत्पन्न होने वाली त्रुटि का निराकरण एवं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 17 नवम्बर को निर्धारित समय पर मतदान कराएंगे और मतदान कराने से पूर्व मॉक पोल कराना अनिवार्य है।

निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ को अथक समर्थन मिलने से भाजपा - कांग्रेस की धड़कने तेज

माही की गूंज, बड़नगर। विजय सोलंकी

बड़नगर विधानसभा चुनाव का जैसे-जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे मुकाबला भी अब काफी रोमांचित होते हुए दिखाई दे रहा है। बड़नगर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस-भाजपा तो मुख्य रूप से चुनाव मैदान में ही है लेकिन इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड को भी जनता का अपार समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि, प्रकाश गोंड द्वारा सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जनसंपर्क किया जा रहा है। इसमें मीठी खेड़ी, जांदला, सेमलिया, अजडावदा आदि समस्त गांव शामिल है। दो निर्दलीय प्रत्याशी सहित चार मैदान में लेकिन निर्दलीय में प्रकाश गोड भारी प्रत्याशी नजर आ रहे है। अब यह तो मतदाता ही तय करेंगे कि कैसे विधानसभा भेजना है लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से भाजपा-कांग्रेस दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी है। बड़नगर में निर्दलीय प्रत्याशि प्रकाश गोड़ की ओर से अथक समर्थन कार्यकर्ता के साथ ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गोड को इस तरह समर्थन मिलना बड़नगर विधानसभा चुनाव मुकाबला काफी और भी रोमांचित होने वाला है।

चोरी गई ट्राली को ले जा रहे बदमाशों को ट्राली मालिक एवं ग्रामिणों ने ट्रेक्टर सहीत पकड़ कर पुलिस के किया हवाले

पुलिस ने दो को भेजा जेल, अन्य आरोपी की तलाश जारी

माही की गूंज, अमझेरा।

ग्राम बान्देड़ी के रहने वाले कृषक जगदीष पुत्र कान्जी रिंगनोदिया की ट्राली दिनांक 6 नवंबर सोमवार की रात्रि में उनके घर से कोई अज्ञात चोर-बदमाश चुरा कर ले गया। जिसकी खबर उन्हे अगले दिन मंगलवार को लगी तो वे ट्राली की खोजबिन में लग गये। उनके साथ अन्य ग्रामिणजन भी ट्राली को खोज रहे थे। तभी शाम के करीब 7 बजे जब वे मांगोदबंगले पर खड़े थे उनके सामने से नीले रंग के ट्रेक्टर के साथ उनकी ट्राली जाती हुई दिखाई दी। जिसे ग्रामिण कांतीलाल लोधा ने ट्रेक्टर चालक को रोकने की कोशिश की लेकिन वाहन नहीं रोकने पर उन्हौने ट्रेक्टर पर चढ़कर वाहन को रोका। वहीं ट्रेक्टर के पीछे बाईक से आ रहे उसके साथी को भी पकड़ कर अमझेरा पुलिस के सुपुर्द किया। जिस पर अमझेरा पुलिस के द्वारा मामले की जांच किये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली एवं बाईक को जप्त कर ट्रेक्टर चालक फरदीन पिता सेहजाद खान व उसके साथ बाईक चालक तनवीर पिता सेहजाद खॉन दोनो निवासी ग्राम जीराबाद को हिरासत में लेकर पुछताछ की गई। जिस पर इनके द्वारा बताया गया कि, उक्त ट्राली उनके एक अन्य साथी रितेश पिता सीताराम निवासी ग्राम खरजूनी के साथ मिलकर चोरी की थी। ग्रामिणों के पास सीसीटीवी फुटेज भी थे जिसमें चोरी गई ट्राली ट्रेक्टर के साथ चुराकर ले जाती हुई दिखाई दे रही थी।

अमझेरा थाने पर जप्त किया हुआ ट्रेक्टर।

अमझेरा थाना प्रभारी संजयसिंह बैस ने बताया कि, उक्त ट्राली चोरी के मामले में दोनो बदमाशों को न्यायालय पेश कर जेल भेजा जा रहा है वहीं अन्य आरोपी रितेष की तलाश कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

अमझेरा थाने पर जप्त की हुई बाईक।

खेतों में खिल रहा सफेद सोना, भाव कम मिलने से कृषक हो रहे मायूस

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में इस समय खरीफ की फसलों की कटाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। मगर खरीफ की फसलों में एक प्रमुख फसल जो कि रबी की फसल के साथ भी रहती है जिसे सफेद सोना कहा जाता है वह सफेद सोना इन दिनों खेतों में अपनी सफेदी की चमकार बिखर रहा है। खिले फूल किसानों के चेहरे की चमक तो बढ़ा रहा है। मगर विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भाव कम मिलने से निराशा भी हो रही है आगामी दिनों में भाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की आर्थिक फसल जो कि खरीफ तथा रबी दोनों सीजन में कृषकों को लाभ प्रदान करती है, वह है कपास की फसल जिसे क्षेत्र में सफेद सोना कहा जाता है। कपास की बुवाई जून-जुलाई माह में खरीफ फसल के साथ की जाती है तथा यह फसल नवंबर दिसंबर में तैयार होने लगती है। कपास के पौधों पर डोडे जब फूल के आकार में खिलते हैं तो खेत में चारों तरफ सफेदी ही सफेदी दिखाई देती है। कपास की फसल की बिनाई तीन-चार बार तक होती है। प्रथम तथा द्वितीय बिनाई (तुड़ाई) में उच्च किस्म का कपास रहता है, इसके बाद फूल हल्का और छोटा होता जाता है। इन दिनों खेतों में कृषक परिवार तथा मजदूर कपास फूल की बिनाई करने में जुटे हैं बाजार में अभी भाव कम मिल रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक वर्तमान में 6500 रूपये कुन्टल के भाव कपास बिक रहा है। जबकि विगत वर्ष यही कपास 75 से 85 रुपए प्रति किलो तक बिक गया था। भाव कम मिलने के कारण कृषक अभी कपास बचने के बजाय घरों में एकत्र कर रहे हैं। ताकि जब भाव अच्छे मिलेंगे तब बेचा जाएगा अभी हाथ खर्च आदि के कारण थोड़ा-थोड़ा कपास (खेरची में) बेचा जा रहा है कृषकों को उम्मीद है कि आगामी दिनों में भाव बढ़ेंगे।

क्या कहते है कृषक व व्यापारी...?

मोटाउमर के कृषक अमरसिंह डुडवे ने बताया कि, कपास की फसल तुड़ाई(बिनाई) प्रारंभ हो गई है कपास की अच्छी किस्म आ रही है मगर भाव कम मिलने से मायूसी है।

अडवाड़ा के कृषक नारायण सिंह चौहान ने बताया कि, बरसात के बाद कपास के फूल नवंबर माह तक खिलने लगते हैं जिन्हें एकत्र करना प्रारंभ किया जाता है अभी कपास एकत्र किया जा रहा है विगत वर्ष की तुलना में भाव कम होने से अभी बाजार में नहीं ला रहे हैं।

थोक अनाज के क्रेता शेख मोहम्मद भाई बोहरा ने बताया, इस सीजन में कपास के भाव पिछले वर्ष की तुलना में कम होने से कृषक अभी कम ही कपास ला रहे हैं भविष्य में अच्छे भाव की उम्मीद की जा रही।

पलायन पर गए मजदूरों को वोट डालने के लिए बुलाने की कवायद...? नेता या प्रशासन कौन होगा सफल...?

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसूरी

वैसे तो जिले में पलायन दशकों से एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जिले की अधिकतर आबादी मजदूरी के लिए यहां से लगातार पलायन करती रही है। हालांकि इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक दिखाई पड़ते है, लेकिन यह प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान भी खड़ा करते दिखाई पड़ते है। वैसे तो जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासन आम तौर पर इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते लेकिन हर चुनाव में इन पलायनकारियों की पूछ परख कुछ खास तरीके से बढ़ जाती है। हर जनप्रतिनिधि और प्रशासन चुनाव के नाम पर अपनी रोटी सेकता नजर आता है। जब-जब चुनाव आते है तब-तब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इनकी याद बहुत ही सताने लगती है। येन-केन प्रकारेण हर जनप्रतिनिधि और प्रशासन इन्हे जिले में वापसी करवाने के भरशक प्रयास करता है। ऐसे ही कुछ हालात इन दिनों भी बने हुए है। राजनीतिक पार्टियां और उनके जनप्रतिनिधि हर चुनाव की तरह इस बार भी इसी कवायद में लगे हुए है कि, किस तरह से पलायन पर गए मजदूर मतदाताओं को मतदान के लिए वापस बुलाया जा सके। कई तरह के प्रयास राजनीतिक पार्टियां और उनके जनप्रतिनिधि करते दिखाई पड़ रहे है। पलायन पर गए मजदूरों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है। उन्हे मतदान करने के लिए जिले में बुलाने को निमंत्रण दिए जा रहे है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से उन्हे आने-जाने की व्यवस्था का आश्वासन भी दिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की कवायद में पलायन पर गए हर मतदाता से जनप्रतिनिधि संपर्क न करते हुए मजदूरों के ठेकेदारों से संपर्क कर रहे है। बताया यह भी जाता है कि, इन मजदूरों को जिले में मतदान के लिए वापस लाने हेतु जनप्रतिनिधि केवल ठेकेदार से चर्चा कर तय रकम के साथ मजदूरों को मतदान के लिए वापस लाने का एक तरह का सौदा करते है। जिसमें मजदूरों के ठेकेदार को हजारों रुपये का भुगतान कर बस या अन्य वाहन उपलब्ध करवाए जाते है जो मजदूरों को पलायन से लाकर मतदान करवाने के बाद वापस उनके कर्तव्य स्थल तक छोड़कर आते है। मजदूरों के ठेकेदार को किया जाने वाला यह भुगतान लगभग 25 से 30 हजार बताया जाता है। इस तरह की सारी कवायदें इस बार भी राजनीतिक पार्टियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है।

हालांकि यह माना जा रहा है कि, दीपावली का त्यौहार एन चुनाव के पहले होने से पलायन पर गए अधिकांश मजदूर मतदाता त्यौहार करने अपने घर को वापसी करेंगे। मगर इसकी पुष्टी कहीं से भी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो जनप्रतिनिधियों को काफी आर्थिक लाभ होने की संभावना है। वैसे तो जिला प्रशासन यहां के मजदूरों को पलायन पर जाने से रोकने के लिए कभी कोई पहल करता आज तक दिखाई नहीं दिया है। मनरेगा जैसी योजना जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, मगर जिले के गरीब आदिवासी को यहां रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके उलट मनरेगा से होने वाले भ्रष्टाचार में अधिकारी, कर्मचारी गंगा नहा रहे है। चुनाव के अलावा पांच साल में प्रशासन कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। हां यह जरूर हुआ कि, कुछ सक्रिय जिला अधिकारियों ने दूसरे प्रदेशों में बंधक बनाए गए मजदूरों को बंधन से मुक्त करवाकर जिले में वापसी करवाई है, लेकिन यह घटना महज एक या दो बार देखने को मिली है। जिले के अधिकांश गरीब आदिवासी अब भी पलायन को मजबूर है। तो कई अब भी किसी प्रदेश में बंधुआ मजदूरी कर रहे होंगे। मगर प्रशासन को इन से कोई सरोकार नहीं है। अब जबकि चुनाव का सीजन आया है तो ऊपर से निर्वाचन विभाग का अधिक से अधिक मतदान करवाने का दबाव होने के चलते प्रशासन इन पलायन पर गए आदिवासी गरीब मजदूरों को फोन कर संपर्क कर रहा है और उन्हे मतदान के लिए निमंत्रण दे रहा है।

वैसे पिछले चुनावों में यह होता आया है कि, जिला प्रशासन की कई टीम पलायन स्थल तक जाती थी और मजदूरों से मिलकर मतदान के लिए आने का न्यौता देती थी। मगर इस बार पलायन स्थल पर टीम भेजने की कवायद शायद प्रशासन ने नजर अंदाज कर दी और पलायन पर गए मजदूरों को सीधे फोन पर ही निमंत्रण दिए जा रहे है। टीम पलायन स्थल पर ना भेजने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि, पलायन पर गए मजदूर दीपावली करने के लिए वापस जिले में आ ही जाएंगे। मगर इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि, कितने लोग त्यौहार करने जिले में वापसी करेंगे।

इस फोन वाली कावयद में प्रशासन को जो जवाब पलायन पर गए मजदूरों की ओर से मिल रहे है, वह भी बड़े रोचक है। भेदियों के जरिए बाहर निकली प्रशासन की यह कवायद और उसके जवाब जब मीडिया में सुर्खियां बने तो प्रशासन की इस कवायद की हवा निकल गई और संपर्क करने वाली टीम के पास मजदूरों के सवालों के कोई जवाब दिखाई नहीं दिए।

बताया यह जाता है कि, कंट्रोल रूम बनाकर जिस टीम को यह काम सौंपा गया है उनके पास महज कुछ हजार लोगों की ही लिस्ट मौजूद है। जबकि जिले से लाखों लोग पलायन कर मजदूरी करने जाते है। एक अंदाजे के मुताबिक यह आंकड़ा करीब दो लाख के आसपास होता है। इस आंकड़े के अुनसार प्रशासन की यह पहल ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती दिखाई पड़ रही है। महज कुछ हजार लोगों की लिस्ट लेकर बैठी टीम जब मजदूरों को वोट डालने का न्यौता देती है तो मजदूरों के द्वारा यह सवाल किया जाता है कि, आने-जाने का खर्च कौन देगा...? इसके जवाब में टीम जवाब यह देती है कि, आपको सवेतनीक अवकाश दिया जाएगा यानि जिस दिन आप छुट्टी पर रहेंगे उस दिन भी वेतन आपको मिलेगा। मगर प्रशासन यहां यह भूल जाता है कि, मतदान के दिन का वेतन तो दिया जा सकता है लेकिन हजारों किलोमीटर का सफर करने में जो दिन लगेंगे उसका पैसा कौन देगा...? क्योंकि जिले से पलायन पर जाने वाले मजदूर गुजरात व अन्य प्रदेशों के आखिरी छोर तक जाते है जिसकी दूरी 500 किलोमीटर से अधिक या हजार किलोमीटर के आसपास होती है। पलायन पर गए मजदूरों को फोन करने वाली टीम से जो सवाल हो रहे है वह भी बहुत ही रोचक है, जैसे- काम छोड़कर आएंगे तो आने-जाने का पैसा कौन देगा...? आप कौन सी पार्टी से बोल रहे है, वोट किसे डालना है...? हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, आ जाएं तो, बन जाएगा क्या...? वाहन की व्यवस्था कौन करेगा, गाड़ी भेज रहे है क्या, सरपंच के चुनाव में तो गाड़ी आई थी...? दीपावली के लिए हम तो पहले से ही आ गए है, अब वोट डालकर ही जाएंगे। कुल मिलाकर प्रशासन की पलायन पर गए मजदूरों को वोट डालने के लिए बुलाने की कवायद महज दिखावा भर साबित हो रही है। अब देखना यह है कि, पलायन पर गए इन मजदूरों को बुलाने में जनप्रतिनिधि कामयाब होते है या प्रशासन..?

थांदला विधानसभाः जीत का रास्ता खवासा क्षेत्र से होकर गुजरता है

माही की गूंज, खवासा।

विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सेनापति तय हो चुके हैं बयानों, आरोपो और आश्वासनो की बौछारें दोनों और से की जा रही है। इन सभी तात्कालिक, प्रादेशिक और देश के मुद्दों के बीच स्थानीय मुद्दे गोण साबित हो रहे हैं। हर उम्मीद्वार अपने प्रादेशिक व आला नेताओं की जुबान ही बोल रहे हैं। 500 की टंकी, एक लाख एक हजार कन्यादान, लाडली बहना के 1250 से बढ़ाकर 3 हजार तक ले जाने के बीच सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं संबंधी दावे नदारत है।

इन बड़े-बड़े दावों के बीच आम जनता आज भी बुनियादी आवश्यकता अधूरी है। चुनाव के समय तात्कालिक मुद्दों की हवा बनती है और हवाओं में बुनियादी मुद्दे दब जाते है। कुछ ऐसा ही मामला ग्राम खवासा की नल-जल योजना का है। आजादी के अमृत काल में जहां हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, वहां विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े ग्राम खवासा में आज भी पेयजल का सामना करना पड़ता है। आम दिनों में 3 से 4 दिन में एक बार और गर्मियों में 20 से 25 दिनों में एक बार जल वितरण होता हैं। वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दलों के दोनों ही प्रत्याशी इस सीट से बारी-बारी से 10-10 साल विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में कोई ठोस कार्य नहीं किया। यही नहीं खवासा में पेयजल के नाम पर बनाई गई 50 लाख रुपए की ढोलखरा तालाब को खवासा लाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और खवासावासियो के हिस्से में आज भी जल संकट बरकरार है लेकिन दोनों ही दल इस मुद्दे पर मोन है।

2018 चुनाव के पहले निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थांदला में देर रात लगभग 1 बजे आयोजित सभा में खवासा में माही का जल लाने की बात कही थी। कोई कार्य योजना नहीं बनी कुछ ऐसी ही घोषणा उन्होंने इस चुनाव में भी देवगढ़ (स्वयं भू माता) में भी खवासा को लेकर की है, जिसको लेकर आम जनता चुटकी लेती नजर आ रही है। आम जनता का कहना है कि, भाजपा यहां 20 वर्षों से (14 माह छोड़कर) सत्ता में लेकिन इसके बावजूद खवासा की पेयजल संकट का हल नहीं कर पाई। जबकि यह क्षेत्र थांदला विधानसभा में हार-जीत का अंतर पैदा करने वाला क्षेत्र है। पिछले कुछ चुनाव का ट्रेड देखे तो इस क्षेत्र से बढ़त लेने वाला उम्मीद्वार ही विजय रहता है।

थांदला विधानसभा को हम तीन भागों में बाटकर आकलन कर सकते हैं। पहला क्षेत्र पलवाड़ क्षेत्र जो गुजरात की सीमा से सटा है, इसमें अनास नदी तक के गांव आते हैं। दूसरा क्षेत्र है मेघनगर क्षेत्र तथा तीसरा क्षेत्र है सुजापुरा घाटे से ऊपर क्षेत्र जो की राजस्थान की सीमा तक और माही नदी के तट तक फैला है। भौगोलिक दृष्टि के साथ ही संस्कृति दृष्टि से भी यह क्षेत्र पलवाड़ क्षेत्र से अलग है। अभी तक जितने भी विधायक बने हैं वो उनमें 50 वर्ष पूर्व केवल राधुसिंह खवासा क्षेत्र के थे। बाकि सभी विधायक मेघनगर, थांदला क्षेत्र के रहे हैं इसलिए इस बार खवासा क्षेत्र से टिकट की मांग उठी थी।

बहरहाल इस बार के चुनाव का आकलन करना राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। चुनाव को 8 दिन बचे हैं लेकिन आम जनता खामोश हैं। इन आठ दिनों में दिवाली का त्यौहार भी लोग अपने काम में मशगूल है। चौराहे पर चुनावी चर्चा सुनाई नहीं दे रही है, ऊपरी तौर पर शांत नजर आ रहे। माहौल प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ा रहा है, भाजपा प्रत्याशी कलसिंह भाभर रोज अलग-अलग गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। अपनी योजना बना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना का बाखल कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं की जा रही है पूरा चुनाव शिवराज सिंह चौहान की योजना के बलबूते लड़ा जा रहा है।

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरसिंह भूरिया 'न काहू से दोस्ती न काहूं से बैर' की तर्ज पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। विपक्षी विधायक होने के नाते वे क्षेत्र में सत्ता विरोधी माहौल तो पैदा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने सरल छवि के बलबूते उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में भी जगह बना ली है। एकला चालो की तर्ज पर वे खुद ही पूरे विधानसभा में घूम कर प्रचार कर रहे हैं और अपनी उपलिब्ध के नाम पर वे टैंकर वितरण और डीपी लगवाना बता रहे हैं। जहां तक अन्य प्रत्याशियों को सवाल है उनकी उपस्थिति ईवीएम पर ही रह सकती है। जयस समर्थिक प्रत्याशी का क्षेत्र में कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। जयस ने गत पंचायत चुनाव में वार्ड क्रमांक 9 में जीतकर जरूर सनसनी फैलाई थी लेकिन इस चुनाव में वैसा कुछ माहौल नजर नहीं आ रहा है। बरहाल इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की ओर से भले ही वीरसिंह और कलसिंह चेहरा हो लेकिन यह चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ ही साबित हो रहा है।

कांग्रेस की सरकार बनी तो सरपंचों, जनपदो और जिला पंचायत सदस्यों को अधिकार पुनः दिए जाएंगेः दिग्विजय सिंह

राजा महाराजा बिक गए लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिका

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

पेटलावद विधानसभा के ग्राम सारंगी में कांग्रेस की जनसभा को दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। पेटलावद विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी वालसिंह मेडा को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। जिसमें उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया, उन्होंने आरोप लगाया की भाजपा द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया लेकिन गरीबों का नहीं किया। उनके द्वारा दावा किया कि, भाजपा सरकार ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है बिजली के बिल हजारों में आ रहे है, जिससे किसान परेशान है। साथ ही यह भी दावा किया कि, भाजपा आदिवासियों का शोषण कर रही है आदिवासियों और गरीबों के हक़ का पैसा लेकर बड़े शहरों में मेट्रो बनाने में लगा रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की 15 माह की सरकार की उपलब्धियां और उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को जनता के समक्ष रखा। साथ ही जनता से यह वादा भी किया कि, जो लोग उनके 15 माह की कांग्रेस सरकारं में कर्ज माफी से चूक गए थे उन लोगों का कर्ज माफ अगली सरकार बनने पर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि, अगर उनकी सरकार बनती है तो बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही गेहूं समर्थन मूल्य पर 26 सौ रूपये क्विंटल खरीदे जाएंगे उन्होंने दावा किया कि, भाजपा ने पंचायत के अधिकारों को छीन कर बड़े अधिकारों के हाथों में दे दिया है। जिन्हें वापस सरकार बनते ही दे दिए जाएंगे कांग्रेस की जनसभा से कार्यकर्ताओ मे उत्साह की लहर दौड़ गई है साथ ही दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए वादों से जनता में भी काफी उत्साह देखा गया।

भाजपा बाहरी नेताओं तो कांग्रेस जनता के भरोसे, बाप कर रहा दोनों को बड़ा नुकसान

विधानसभा चुनाव में नही दिख रही कोई खास हलचल, कई गांवों तक प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर तक नही पहुंचे

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

विधानसभा चुनावो के लिए 17 नम्बर को वोट डालने है, लेकिन इससे पहले यहां चुनाव को लेकर कोई खास हलचल या चहल-पहल तक नही देखी जा रही। विधानसभा के एक्का-दुक्का बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोगों को ये तक पता नही की चुनाव कौनसा हो रहा है और कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के अलावा तीसरा नाम लोगो के कानों ओर दरवाजों तक बाप पार्टी के बालू सिंह गामड़ का पहुचा है। बाकी 5 प्रत्याशी जो हैं वो कुछ खास करते नही दिख रहे , आप पार्टी के लोग सोशाल मीडिया पर थोड़ी बहुत हलचल बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास प्रचार-पसार नही दिख रहा। पूरा चुनाव पूरी तरह से सुस्त है और दोनों मुख्य दलों के कार्यालय तक, मुख्यालय के अलावा ज्यादा जगह नही खुले हैं। आम जनता की नजर से अब तक का चुनावी माहौल निराशाजनक रहा है। जहां कोई खास प्रचार-प्रसार नही होता दिख रहा और क्षेत्र के मुद्दे पूरी तरह से गायब है जिनकी बात कोई नही कर रहा। दीपावली के 5 दिन बाद मतदान होना है और फिलहाल लोग दीपावली को लेकर तैयारियो में जुटे हैं जिसके चलते चुनावी रंगत फीकी है और फीकी ही रहने की उम्मीद् है क्योंकि दीपावली के बाद प्रचार-प्रसार का समय तक नही बचा रहा है।

स्थानीय कार्यकर्ता बेरोजगार, बहारी नेता की जय-जय कार

बात करे भाजपा की तो पूरी तरह बहारी नेताओं के भरोसे चुनाव मैदान में दिख रही है। भाजपा संगठन गुजरात पैटर्न पर चुनाव मैदान में दिख रही हैं, जिसके चलते स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता केवल भाजपा के पैटर्न वोटर बनकर रह गए हैं। भाजपा ने चुनाव से पहले संकल्प ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ अध्यक्ष ओव सात बूथ पर एक शक्ति केंद्र बना कर जमीनी तैयारी की थी। भाजपा संगठन उसी संरचना के हिसाब से अपनी तैयारियों में जुटा है। हर विधानसभा में अन्य राज्यो की टीम शक्तिकेन्द्र की संख्या के हिसाब से आई हुई है जो शक्ति केंद्र के अध्यक्ष के माध्यम से बूथ अध्यक्ष तक ओर बूथ अध्यक्ष के माध्यम से मतदाता तक पहुँच रही है। पेटलावद विधानसभा के लिए गुजरात से लगभग 50 लोगो की टीम इस कार्य मे लगी हुई है। भाजपा की इस तैयारी के कारण क्षेत्र, नगर कई बड़े ओर पुराने नेता केवल मूक दर्शक बनकर चुनाव देख रहे हैं। तो कुछ नेताओं को नए-नए पद देकर प्रभारी बनाकर नेता होने का अहसास करवाया जा रहा है। उधर संगठन में ओबीसी, अजा, अजजा मोर्चे के गिने-चुने नेता भीड़ बढ़ाते देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार भाजपा संगठन के भरोसे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के साथ मैदान में उतरी है। भाजपा प्रत्याशी की और से कार्यकर्ताओ की अनदेखी की खबरे भी लगातार सामने आ रही है। मण्डल स्तर तक के नेताओं के चुनाव में कोई बड़ी जबाबदारी नही है।

कांग्रेस जनता के भरोसे, बाप का दावा चुनाव जीतेंगे

भाजपा अपने नए कागजी संगठन तो कांग्रेस पूरी तरह जनता के भरोसे दिख रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा की 18 साल की सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप करते हुए ही चुनाव मैदान में है इतना ही कांग्रेस जनता के भरोसे मैदान में दिख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि, भाजपा से त्रस्त जनता 2018 की तरह इस बार भी सरकार बनवा देगी। कांग्रेस के ज्यादातर मुद्दों पर भाजपा घोषणाये कर रही है या फिर योजना बनाकर पेशकर दी है। कांग्रेस में भितरघात की बढ़ती संभावना और जयस समर्थित भारत आदिवासी पार्टी के बालूसिंह गामड़ के मैदान में होने से कांग्रेस के समीकरण फिलहाल बिगड़े हुए लग रहे हैं। अगर उम्मीद् से ज्यादा मतदाता बाप पार्टी की ओर मुड़ा तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी की उपस्थिति कही न कही भाजपा के लिए भी चुनौती बनती जा रही। युवा वोटरों का झुकाव ज्यादातर भाजपा की ओर रहा है लेकिन जयस समर्थित युवा भाजपा के खेमे में जाता नही दिख रहा है। रामा क्षेत्र से होने वाले मतदान का महत्व बढ़ गया है जो कही न कही भाजपा और कांग्रेस का गढ़ रहा है।

नेताओ की सभा मे व्यस्त दोनों दल, पलायन पर आज भी ग्रामीण

विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान यहां इसलिए भी फीका दिख रहा है क्योंकि यहां दोनों दल के नेता क्षेत्र की होने वाली सभाओं की तैयारी में लगे हुए है। कांग्रेस की और से पुर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह तो भाजपा के लिए बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने सभा की। सभा मे ज्यादातर भाजपा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आम जनता इन सभाओं में न के बराबर पहुच रही है। दीपावली ओर क्रिकेट वर्ल्डकप के बीच चुनाव की रौनक उस स्तर की नही रही जिस स्तर की होनी थी। बड़ी मात्रा में आज भी ग्रामीण पलायन पर है जो दीपावली के एक-दो दिन पूर्व तक आने की संभावना हैं। दीपावली बाद वोट के लिए कितने मतदाता रुकते हैं ये देखना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार दिख रहा है वही चला तो ग्रामीणो के वापस काम पर लौटने की संभावना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422